स्वदेशी पत्रिका

o"k&21] vad&7] vk"kk<&Jko.k 2070] tqykbZ 2013

संपादक
foØe mikè;k;
dk;kZy;
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

vkoj.k dFkk&4

वित्तमंत्री पी. चिदंबरम कह रहे हैं, खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने के बावजूद सरकारी खजाने पर जीडीपी का एक फीसदी से अधिक खर्च नहीं आएगा। जबकि गणित कहता है कि जीडीपी का तीन फीसदी इस पर खर्च होगा। हम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम को खुली चुनौती देते हैं . . .

doj ist

अनुक्रम

vkoj.k dFkk
चोरी छिपाने के लिए चोर दरवाजे से अध्यादेश
& lqjthr ,l HkYyk /4
सड़ी गड़ी वितरण प्रणाली भरोसे खाद्य सुरक्षा
& Mk- vf'ouh egktu /6
nsoh; vkinк
उत्तराखण्ड में प्राकृतिक प्रकोप : विकास बना विनाश का कारण
& Mk- lR;sUnzdqekj vxzoky /8
आपदा की त्रासदी के सबक
& vo/ks'k dqekj /11
fo'ys"k.k
विकास की विभीषिका & Mk- Hkjr >qu>quokyk /14
vFkZO;oLFkk
बदहाली अर्थव्यवस्था के गुनहगार
& cyohj iqat /24
fopkj
सिर्फ बातों से नहीं उठेगा रुपया
& vkyksd iqjkf.kd /26
nf"Vdks.k
घट रही है विकास दर, बढ़ रही बेरोजगारी
& t;zhyky HkaMkjh /28
i'kq/ku
देसी दूध व्यापार पर विदेशी कुचक्र
& Hkkjr Mksxjk /29
eqn~nk
जारी है अघोषित आपातकाल
& vjfoUn t;fry /31
varjk"Vªh;
दब्बूपने से नहीं चलने वाला है काम
& Mk- oniizrki oSfnd /34
ikBdukek@2] lekpkj ifjØek@28] jiV@36

पाठकनामा

अंधाधुंध विकास ने रची तबाही

आज उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण जन–माल की भारी क्षति हो रही है। माना हिमालय और मानसून का गहरा संबंध है। समय से पूर्व मानसून का आगमन खतरे का संकेत होता है। ऐसा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण होता है। विकास के नाम पर हिमालय में बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया जा रहा है, बेतहाशा विस्फोटकों का इस्तेमाल पहाड़ काटने के लिए किया जा रहा है, लंबी–लंबी सुरगें बनाई जा रही है, बांध बनाएं जा रहे है, बिजली उत्पन्न की जा रही है। जिसके कारण आज हिमालय कमजोर हो गया है। देखा जाए तो यह मानव निर्मित आपदा है। लेकिन सरकार इसे प्रकृति या दैवी आपदा कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। यह स्वार्थ, लालच और भ्रष्टाचार के बोये बीज की उपज है, इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए ताकि देवभूमि को बचाया जा सके।

& jkd'k dekj ik.M;] xyh u- 11] djrkj uxj] fnYyh

दैवीय आपदा के प्रकोप में उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड दैवीय आपदा में तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए राज्य सरकार और अन्य राज्यों की सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया। परन्तु गाँव वालों के बारे में कोई सुध नहीं ले रहा है। कई गाँवों में काफी नुक्सान हुआ है। वैसे भी पहाड़ों पर जीवन जीना कोई आसान काम नहीं है। अधिकतर गांवों के पुरुष वर्ग शहरों में रोजगार करते हैं। फलस्वरूप गांव में स्त्री और बच्चों के साथ–साथ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती है। इन लोगों के पास मुश्किल से दस–पन्द्रह दिन का अनाज ही होता है, अब वो अनाज भी खत्म हो गया होगा। क्या वे खाएंगे और कैसे जीवित रहेंगे – राज्य सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। माना दैवीय आपदा पर किसी का वश नहीं होता, परन्तु दुख की घड़ी में राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्था ही उनका सहारा है। जरूरत है अब गांव वालों पर राज्य सरकार और स्वयंसेवी संस्थान ध्यान दें जिससे गाँव वाले इस मुश्किल घड़ी से निकल सकें।

& thou flg] Jhjke feyfu;e Ldy] ,l&1] lDVj&135] uk,Mk

गरीबों की हितैषी या चुनावी हथकंडा

वर्तमान समय में देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने पर केंद्र सरकार अड़ तो गई है, लेकिन इसका खामियाजा शायद अगली सरकार को उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार का यह फैसला आने वाली नई सरकार पर करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का बोझ डालने जा रहा है। जबकि जानकारों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक का असर अर्थव्यवस्था पर सरकार की उम्मीदों से भी ज्यादा होगा क्योंकि यह फैसला घरेलू स्तर पर खाद्यान्न बाजार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और अब सवा लाख करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी! क्या देश की अर्थव्यवस्था वहन करने की स्थिति में है? इस योजना से गरीब का भला न हो परन्तु अर्थव्यवस्था का जरूर बेड़ा गर्क होगा।

& vej'k dekj] vk;k uxj] fnYyh

vko';d ugh fd bl vd d Hkhrj iLrr y[kdk d fopkj Lon'kh if=dk d liknd eMy d fopkjk l ey [kkr gkA ikBdk dh tkudkjh d fy, mUg ;gk iLrr fd;k tk jgk gA

संपादकीय कार्यालय

^^èke{k= f'ko 'kfDr efUnj] lDVj&8] jkeÑ".kije] u;h fnYyh&110022**

njHkk"k % 011&26184595 Û b&ey % swadeshipatrika@rediffmail.com

vxj vki ?kj cB Lon'kh if=dk pkgr g rk fMekM Mk¶V] euhvkMj vFkok pd }kjk 'kYd ***^Lon'kh if=dk*** **fnYyh d uke Hkstu dk d"V djA**

okf"kd lnL;rk 'kYd % 150 #i,
vkthou lnL;rk 'kYd% 15]00 #i,

;fn 'kYd Hkstu d mijkr Hkh vkidk if=dk le; ij miyCèk ugh gk ik jgh g rk rjr if=dk dk;ky; dk lfpr djA

;k vki lhèk cd vkQ bfM;k] [kkrk u- 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 ¼Ramakrishnapuram½

उन्होंने कहा

राहत और बचाव की जिम्मेदारी सरकार पर है। ऐसे में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री को जनता को संतुष्ट करना चाहिए। उनका अपना स्वभाव है जो हम नहीं बदल सकते, लेकिन वह जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

& xkfoUn flg dtoky]
foèkku lHkk vè;{k mÙkjk[k.M

धमाके नहीं होंगे, यह दावा कोई नहीं कर सकता। हम लोग जमीन से जुड़े हैं और आसमान पर हमारी पकड़ नहीं है। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ।

& uhrh'k dekj

सीबीआई निदेशकों की भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस के साथ साठगांठ एक बात है, लेकिन सुरक्षा के ढांचे को बर्बाद करने के लिए सीबीआई कांग्रेस के साथ जो साठगांठ कर रही है उसके बहुत गंभीर नतीजे देश को झेलने होंगे।

& ih;"k dyJ"B

यदि राजनैतिक दल सार्वजनिक हित के अलावा और चीजों का वायदा करना चाहते हैं तो उन्हें यह बताने की बाध्यता होनी चाहिए कि वे इनके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाएंगे।

& Vh,l Ñ".kefr]
io e[; pquko vk;Dr

सुप्रीम कोर्ट ने फिर साबित कर दिया कि सुधारों के लिए वह आखिरी दरवाजा है। संकीर्ण स्वार्थों वाले तब तक कोई बदलाव नहीं होने देंगे जब तक उनके पास कोई विकल्पहीनता की स्थिति नहीं आ जाती।

& fdj.k cnh

jlkry eas #i;k

डॉलर की आंधी में रुपया उड़ता जा रहा है। उसे थामने वाले की जिम्मेदारी रखने वाले लोग बंगले झांक रहे हैं। प्रधानमंत्री चिदंबरम की ओर देख रहे हैं और चिदंबरम रिजर्व बैंक के गवर्नर की तरफ। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम अलबत्ता मीडिया को यह समझाने में लगे हैं वह लोगों में दहशत न पैदा करें। बकौल वित्तमंत्री यह अपेक्षा के अनुरूप ही हो रहा है। विश्व की कई मुद्राएं इस समय हिचकोले खा रही है। भारतीय रुपया का अवमूल्यन हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। तब जबकि तीन महीने में रुपये अपनी कीमत 13 फीसदी खो चुका है। वित्तमंत्री के लिए यह संकट कोई बड़ी बात नहीं पर देश के लिए तो है। हम केवल अपने रुपये का मूल्य नहीं खो रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के प्रति अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। जिस तेजी से रुपया अपना मूल्य खोता जा रहा है, उससे जल्दी ही देश में विदेशी मुद्रा के भंडार का टोटा पढ़ जाएगा। रुपये को बचाने के लिए रिजर्व बैंक को बाजार में दबा कर डॉलर बेचने पड़ रहे है और दूसरी तरफ हमारा आयात का बिल लगातार बढ़ रहा है। खासकर पेट्रोलियम कंपनियां चिल्ला रही है। रुपये की कीमत में एक रुपये के अवमूल्यन से पेट्रोलियम कंपनियों पर रोज ही 6000 करोड़ रुपये की मार पड़ रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के सुब्बा राव मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वे भी बैठकों के जरिए हालात का जायजा भर ले रहे हैं। और भुगत जनता रही है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि रोजमर्रा की बात हो गई है। दो हफ्ते में ही पेट्रोल पांच रुपये तक महंगा हो गया है। कहते हैं कि अमरीका की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया गिर रहा है। एक वास्तविकता यह भी हो सकती है। पर सत्य यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से खराब हो रही है और बाहरी निवेशक यहां से पैसे निकाल कर ले जा रहे हैं। सरकार कोई ठोस उपाय के बजाय यह सलाह दे रही हैं कि लोग बाहर से सोना आदि न खरीदे। आयात कम कर दें और बाहर की दुनिया से कुछ दिनों के लिए कट जाएं। सोना भी तो रोज टूट रहा है। संकट के दिनों के लिए सोना सहेज के रखने वालों के दिल पर अब तो सांप लोट रहा है। उनकी पूंजी डूबती नजर आ रही है। बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जरूरी है कि कोई नीतिगत उपाय किए जाए। हालांकि इस बात की आहट सुनाई दे रही है कि विदेशी निवेश के लिए सरकार कुछ नए क्षेत्र खोल रही है और कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने जा रही है। पर यह दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है। सरकार की पिछली घोषणाओं पर विदेशी निवेशकों ने बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दी है। न तो खुदरा क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश आया और न कोई ब़डा विलय या अधिग्रहण का प्रस्ताव आया। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यस्था के प्रति बाहर के निवेशकों में उदासीनता बढ़ गई है। इसके लिए स्वयं यह सरकार जिम्मेदार है। बिना किसी उचित प्रावधान के चुनावी घोषणाएं किए जा रही है। कहा जा रहा है कि मनरेगा और किसानों की कर्ज माफी की भरपाई अभी हुई नहीं हुई कि खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस चुनाव को ध्यान में रखकर ले आई है। अभी से ही यह कयास लगाया जा रहा है कि 65 फीसदी जनता के साथ या तो सरकार सिर्फ धोखेबाजी कर रही है, या चुनावी नारे के लिए लाखों करोड़ रुपये का बोझ सरकारी खजाने पर लादने जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ यह खिलवाड़ आखिर जनता पर ही भारी पड़ रही है। कार, फोन, गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ेंगी। किसी भी ब्याज कटौती की संभावना अब न के बराबर होगी, आयातित कच्चे माल पर आधारित उद्योग बंद होंगे। राजस्व घाटा लगातार बढ़ता जाएगा। यह भी आशंका है कि आने वाले दिनों में भारत की निवेश रेटिंग काफी नीचे चली जाएगी। बाहर जाकर उद्योग धंधे लगााने में काफी कठिनाई आएगी। सरकार को चाहिए कि इन परिस्थितियों से तुरंत बाहर निकलने के लिए कार्य बल बनाए। मुद्रा बाजार में सक्रिय सट्टेबाजों पर लगाम लगाए। मुद्रा के वायदा बाजार और फ्यूचर ट्रेडिंग पर कड़ी नजर रखी जाए। निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि संकट की इस घड़ी में विदेशों में जमा अपने डॉलर भारत लेकर आए। पर इसके लिए सरकार खुद को विश्वसनीय सिद्ध करे।

आवरण कथा

चोरी छिपाने के लिए चोर दरवाजे से अध्यादेश

[kk| lqj{kk v/;kns'k ykdj viu Hkz"Vkpkj dk Niku dh dkxzsl dh dksf'k'k

foÙkeaU=h ih- fpnEcje dg jgs gSa] [kk| lqj{kk foèks;d ykxw gksus ds ckotwn ljdkjh [ktkus ij thMhih dk ,d QhlnhA l s vfèkd [kpZ ugha vk,xkA tcfd xf.kr dgrk gS fd thMhih dk rhu Qhlnh bl ij [kpZ gksxkA ge lkfu;k xkèkh] euekgu flag vkSj ih fpnEcje dk [kqyh pqukSrh nsrs gSa fd og crk,a fd fdl rjg ls [kk| lfClMh bruh de vk,xh ftruh os crk jgs gSaA

■ सुरजीत एस भल्ला

[kk| सुरक्षा विधेयक, माफ कीजिए आपात अध्यादेश, को यदि ईमानदारी से लागू किया जाए तो पहले साल में ही इस पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के तीन फीसदी के बराबर लागत आएगी।

हमें इस अति असामान्य फैसले को लेकर बड़ी जल्दी थी। चूंकि भाजपा ने संसद चलने नहीं दिया इसलिए संविधान में सरकार को अध्यादेश लाने का जो अधिकार वर्णित है उसका हमने तत्काल उपयोग कर लिया।

विधेयक, माफ कीजिए, अध्यादेश का मकसद गरीबों को खाना उपलब्ध कराना बताया जा रहा है, ताकि गरीबी का उन्मूलन किया जा सके। कांग्रेसियों के अनुसार सोनिया गांधी का यह सपना है,

;kstuk dk ykxw dk ,d izeq[k dkj.k ;g gS fd blds tfj, dkaxzsl viuk lkjs Hkz"Vkpkj vkSj ?kksVkyks ij ijnk Mkyuk pkgrh gSA dkaxzsl ds yksx lkprs gSa fd ;g pqukoh lky gS vkSj turk mudsa fd, dks ekQ dj nsxhA lkfu;k xkaèkh blhfy, bl foèks;d dks ykus ds izfr T;knk mrkoyh gSaA

और इसे वर्ष 2009 के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल भी किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता की माने तो यह कदम गरीबी खत्म करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह गरीबों को पांच किलो चावल, तील रूपये गेहूं और एक रुपये किलो अन्य खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देगा। यह कानून उसी प्रारूप और प्रेरणा के साथ लागू किया जाएगा जिस तरह 2005 में रोजगार गारंटी कानून पास कराया गया था। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि यह नई योजना ग्रामीण इलाके में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेहद जरूरी थी और पहली बार गरीबों के लिए कोई ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। कंग्रेस ने यह कभी नहीं बताया कि सरकार द्वारा वित्त पोषित रोजगार गारंटी योजना 1980 के दशक के शुरूआत में ही महाराष्ट्र में लागू हो गई थी और तब से केंद्र सरकार की योजनाओं में यह शामिल भी रही है। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा विधेयक भी 1970 के उत्तरार्द्ध में केंद्र द्वारा लागू जन वितरण प्रणाली का एक अग्रेसित योजना भर है।

इस योजना को लाने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसके जरिए कांग्रेस अपने सारे भ्रष्टाचार और घोटालों पर परदा डालना चाहती है। कांग्रेस के लोग सोंचते हैं कि यह चुनावी साल है और जनता उनके किए को माफ कर देगी। सोनिया गांधी इसीलिए इस विधेयक को लाने के प्रति ज्यादा उतावली हैं। यदि इसे नीतिगत फैसला माने तो पहले सरकार को यह आकलन करना होगा कि जन वितरण

प्रणाली और रोजगार गारंटी योजना से देश को क्या लाभ हुआ और उसे जनता को बताना होगा।

कांग्रेसी यह दावा करते हैं कि जिस तरह से मनरेगा के तहत गरीबों को रोजगार प्राप्त करने के कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं उसी तरह से खाद्य सुरक्षा विधेयक से भी गरीबों को भोजन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जनता चाहेगी तो खाद्य सुरक्षा और रोजगार गारंटी को लेकर सरकार को भी कानूनी कठघरे में खड़ा कर सकती है। वाह! निश्चित रूप से यह दुनिया का सबसे उत्तम लाभकारी योजना है, और भारत खासकर कांग्रेस को इस पर गर्व होना चाहिए।

मनरेगा या नरेगा वर्ष 2005–06 से ही लागू है, बल्कि 2008–09 से तो पूरे देश में लागू हैं। यानी सरकार के पास रोजगार के मामले पांच साल का ठोस अनुभव उपलब्ध है। आज तक न तो किसी गरीब ने और न अमीर ने सरकार को रोजगार देने के मामले में कठघरा मे खड़ा किया है। तो यह माना जाए कि रोजागर गारंटी योजना से गरीब पूरी तरह संतुष्ट है और उन्हें कूनन के प्रावधान के अनुसार कम से कम 100 दिन के रोजगार मिले हैं।

सरकार के अनुसार दो तिहाई से अधिक लाभार्थी 2009–10 में गरीब नहीं रह गये और उनका औसत उपभोग लाभार्थियों पर होने वाले खर्च से भी 50 फीसदी अधिक बढ़ गया और ये अगरीब लोग ही नरेगा के तहत काम पाने वाले तीसरे प्रमुख लोग हैं। इससे तो यही पता चलता है कि नरेगा में जबर्दस्त भ्रष्टाचार है या यूँ कहें कि इसे बनाया ही इस तरह गया है कि इसके तहत गैर कूननी या गलत काम किया जा सके। यही कारण है कि गरीबों के लिए काम मुहैया न होने के बावजूद कोई कानूनी लड़ाई लड़ने सामने नहीं आता। यहां तक कि सरकार भी मान चुकी है कि नरेगा में बहुत भ्रष्टाचार है और पिछले पांच वर्ष में एक वर्ष भी इस मद में आवंटित राशि पूरी खर्च नहीं हो सकी है। इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि नरेगा में भ्रष्टाचार को घुसाया गया है।

eujxk ;kstuk o"kZ 2005&06 ls gh ykxw gS] cfYd 2008&09 ls rks iwjs ns'k esa ykxw gSA ;kuh ljdkj ds ikl jkstxkj ds ekeys ikap lky dk Bksl vuqHko miyC/k gSA vkt rd u rks fdlh xjhc us vkSj u vehj us ljdkj dks jkstxkj nsus ds ekeys esa dB?kjk esa [kM+k fd;k gSA

अब बात इस खबर पर ''अध्यादेश के जरिए शासन'' वल्लाह! जन वितरण प्रणाली के जरिए खाद्य सुरक्षा यानी राशन के अनाज का कई गुणा वितरण यानी साफ है नरेगा से भी कई गुणा भ्रष्टाचार का रास्ता। हाल ही नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा 2011–12 के लिए उपभोक्ता खर्च के आकड़े जिसमें यह दर्शाया गया था कि जब खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू हो जाएगा, और होगा भी आखिर कांग्रेस, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सम्मानित लोग हैं और वे अपनी बात पर टिकेंगे ही, तो खाद्य सब्सिडी कितनी हो जाएगी, को आधार बनाकर आकलन करे।

मान लिया कि इस विधेयक के आने से पहले खाद्य सब्सिडी 100 रुपये है, और नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 45 फीसदी लोग जन वितरण प्रणाली के तरह खाद्यान्न लेते हैं विधेयक के कानून बनने के बाद 67 फीसदी लोग इस प्रावधान का लाभ उठाएंगे। तब सब्सिडी होगी 100x67/44.5 यानी 150। अब एनएसएस के आकड़े के अनुसार अभी प्रति व्यक्ति पीडीएस अनाज की उपलब्धता 2.1 किलोग्राम है। विधेयक के कानून बनने के बाद यह पांच किलो हो जाएगा। यानी सब्सिडी में बढ़ोतरी होगी 150x5/2.1 या 357।

चूंकि सोनिया गांधी की यह अति महत्वकांक्षी योजना है इसलिए यह लागू होगी ही, इसलिए जरूरी है कि अनाज का बाजार मूल्य लिया जाए। यह मान लेते हैं कि खाद्यान्न पर आने वाली सब्सिडी 13.5 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 16.5 रुपये प्रति किलो हो जाएगी। यह तब जब हम खाद्यान्न के बाजार मूल्य को 19 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रखते हैं। अब बढ़ी हुई सब्सिडी होगी 357x16.5/13.5 यानी 436।

सरकार के आकड़े के अनुसार वर्ष 2011–12 में खाद्य सब्सिडी थी 72,000 करोड़ रुपये अतः इस विधेयक के पास होने के बाद यह सब्सिडी बढ़कर हो जाएगी 72,000x436 यानी 3,14,000 करोड़ रुपये, जबकि कांग्रेसी और वित्तमंत्री पी. चिदंबरम कह रहे हैं, खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू होने के बावजूद सरकारी खजाने पर जीडीपी का एक फीसदी से अधिक खर्च नहीं आएगा। जबकि गणित कहता है कि जीडीपी का तीन फीसदी इस पर खर्च होगा। हम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम को खुली चुनौती देते हैं कि वह बताए कि किस तरह से खाद्य सब्सिडी इतनी कम आएगी जितनी वो बता रहे हैं।

¼lHkkj % bfM;u ,Dlizsl½

सली गड़ी वितरण प्रणाली भरोसे खाद्य सुरक्षा?

lkotfud forj.k i.kkyh e lekkj gr l>kok tl& QM LVEi] d'ky icekku] ikjnf'krk vkj foLrr igp bR;kfn dk tl jnnh dh Vkdjh e Mky fn;k x;k gA vPNk gkrk fd ljdkj xjhck dk [kk| diu vFkok QM LVEi tkjh dju dk ikoèkku cukrhA ,l e xjhc lèk cktkj l bld eke;e l vukt y ikrA bll fjlko Hkh lekIr gkrk vkj ljdkjk dk HkMkj.k leL;kvk l Hkh futkr fey ikrkA

■ डॉ. अश्विनी महाजन

vrkRxRok केन्द्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। लेकिन नया खाद्य कानून पुरानी और जर्जर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर ही आधारित है। देश में अनाज, कैरोसिन, चीनी आदि का वितरण देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर आधारित है। एक समय था, जब देश में हर परिवार का एक राशन कार्ड होता था। इस राशन कार्ड से हर परिवार को उचित कीमत पर अनाज, कैरोसिन, चीनी और कभी–कभी प्याज, दालें आदि भी मिला करती थी। राशन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में जाना जाता था।

समय बदला राशन कार्डों का रूप भी बदल गया। गरीबों को बी.पी.एल. कार्ड जारी करने की कवायद शुरू हुई और अन्य जरूरतमंदों को गैर बीपीएल कार्ड जारी होने लगे। सामान्य गृहस्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर हो गए। हालांकि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा राशन दुकानों से सस्ता सामान लेने से वंचित हो गया, लेकिन खाद्य सब्सिडी पर सरकारी बिल लगातार बढ़ता गया।

22 साल पहले केन्द्र सरकार की खाद्य सब्सिडी, जो मात्र 2450 करोड़ रूपए थी, 2012–13 तक में 85000 करोड़ तक पहुंच गई। खाद्य सब्सिडी का बोझ इस कारण से नहीं बढ़ रहा था कि सरकार पहले से ज्यादा और बेहतर अनाज इत्यादि लोगों तक पहुंचा रही थी, बल्कि इसलिए आजादी के बाद अपनाई गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिचालन लागत बढ़ रही थी। चौंकिए नहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एक रूपया लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सरकार का खर्च 3.65 रूपए है। ये आंकड़े भारत के योजना आयोग के हैं।

u;k [kk| lj{kk dkuu

यूपीए सरकार की अगुवाई कर रही कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा था कि वे देश में एक नया खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आएंगे, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार लोगों को मिल जाएगा। वर्तमान यूपीए सरकार के साढ़े तीन वर्ष गुजर चुके हैं और इस बीच खाद्य सुरक्षा संबंधी विधेयक के कई मौसेदे चर्चा में आते रहे। पहले यह कहा गया था कि देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या को इस कानून के दायरे में लाया जाएगा, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने और अंतोत्गत्वा संसद के पटल पर रखने तक इसे ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत तक सीमित किया जा चुका था। माना जाता है कि इस आधार पर देश की कुल 63.5 प्रतिशत जनसंख्या को ही इसका लाभ मिलेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए भी मुफ्त भोजन का प्रावधान इस विधेयक में है। दिखने में प्रस्तावित कानून अभी तक की व्यवस्था से बेहतर दिखाई देता है, लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए भी वही पुरानी सली गड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सहारा लिया जा रहा है, जिसमें अकुशलता, भ्रष्टाचार, रिसाव (लीकेज) जैसी सारी बीमारियां बदस्तूर जारी रहने वाली हैं।

n'k e dik"k.k vkj Hk[k feVku dh egrh t:jr g] yfdu lkFk gh lkFk ml 0;oLFkk dk Hkh n:Lr dju dh t:jr g] ftll ;g edln iwjk gkuk gA llln e iLrkfor fcy e dgk x;k fd bl dkuu dk ykx dju d fy, ftru Hkh t:jh vukt dh vkifr djuh gkxh- - -

देश में कुपोषण और भूख मिटाने की महती जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ उस व्यवस्था को भी दुरूस्त करने की जरूरत है, जिससे यह मकसद पूरा होना है। संसद में प्रस्तावित बिल में कहा गया कि इस कानून को लागू करने के लिए जितने भी जरूरी अनाज की आपूर्ति करनी होगी, वह सब केन्द्र सरकार उपलब्ध कराएगी, लेकिन उसके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकारों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली

में अकुशलता, भ्रष्टाचार, लाभार्थियों की सही पहचान का अभाव और अनाज की बर्बादी के साथ अलग–अलग स्तरों पर लीकेज खाद्य सुरक्षा के मकसद को ही झूठला सकती है।

dSls gksxh ykHkkfFkZ;ksa dh igpku!

संसदीय समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार गरीबी की बहुआयामी एवं विस्तृत अवधारणा ले, ताकि गरीब की पहचान सही ढंग से हो सके। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि गरीबी के आकलन एवं गरीब की पहचान के बारे में सरकार द्वारा वर्तमान में जो प्रणाली अपनाई जाती है, उसके अनुसार गरीबी के सरकारी अनुमानों एवं गरीबी के वास्तविक आपात में भारी अंतर आ गया है।

मापदंड के आधार पर गरीबों की संख्या में भारी अंतर दिखाई देता है। संसदीय समिति ने इस संबंध में विभिन्न विशेषज्ञ दलों द्वारा किये गये अनुसंधान की विवेचना करते हुए यह पाया कि हर मापदंड के आधार पर गरीबी के अनुमान भिन्न–भिन्न दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रो. तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल के अनुसार कैलोरी उपभोग के आधार पर 37.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीब कहलाई (2004–05), वहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय की सक्सेना कमेटी के अनुसार 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीब की श्रेणी में है, जबकि अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार यदि कार्य एवं आजीविका की स्थितियों के आधार पर देखा जाये तो 77 प्रतिशत जनसंख्या गरीब कहलायेगी। इसलिए समिति ने सुझाव दिया था कि गरीब की पहचान एवं आकलन हेतु अपनाये जा रहे मापदंड को केन्द्र, राज्य सरकारें एवं स्थानीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयास द्वारा इस प्रकार से बनाया जाये ताकि गरीबी की सही एवं एकरूप माप हो सके।

लाभार्थियों की पहचान तो दूर अभी उनके पहचान के मानक भी तय नहीं हो पाए हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने इस बाबत अपना पल्ला झाड़ते हुए इस काम का जिम्मा राज्य सरकारों को देने का प्रावधान प्रस्तावित कानून में किया है।

किस राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को कितने प्रतिशत ग्रामीण और कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ मिल पाएगा, यह तो केन्द्र सरकार तय करेगी, लेकिन उसके दायरे में कौन आयेंगे यह तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। गरीब की पहचान करते हुए बीपीएल राशन कार्ड जारी करने की व्यवस्था के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा गठित सक्सेना कमेटी का यह कहना है कि देश में 50 प्रतिशत वास्तविक गरीब लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं और 40 प्रतिशत बीपीएल कार्डधारक वास्तव में गरीब नहीं हैं। इस परिस्थिति में सभी जरूरतमंदों की भूख शांत करना तो संभव है ही नहीं, साथ ही यह प्रणाली भारी लीकेज को जन्म देने वाली होगी।

dsUæ ljdkj }kjk xfBr lDlsuk deVh dk ;g dguk gS fd ns'k esa 50 izfr'kr okLrfod xjhc yksxksa ds ikl chih,y dkMZ ugha gSa vkSj 40 izfr'kr chih,y dkMZèkkjd okLro esa xjhc ugha gSaA bl ifjfLFkfr esa lHkh t:jrenksa dh Hkw[k 'kkar djuk rks laHko gS gh ugha] lkFk gh ;g iz.kkyh Hkkjh yhdst dks tUe nsus okyh gksxhA

dgk¡ ls yk;sxs jkT; blds fy, iSlk!

हालांकि खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्यवन हेतु समस्त अनाज केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराया जायेगा, लेकिन राज्यों से यह अपेक्षा रखी गई है कि वे यह सुनिष्चित करेंगे कि वे अनाज लक्षित लोगों तक पहुंच जाए। इसका मतलब यह है कि वे इसके लिए राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भंडारण और ट्रांस्पोर्ट सुविधाएं अपने खर्चे से करेंगे। इस विषय में देरी अथवा कोताही होने पर राज्यों अपने खजाने से खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होगा। राज्यों को इस विधेयक से सबसे बड़ी षिकायत यह है कि यह विधेयक इस संबंध में राजस्व जुटाने के प्रति मौन है। इसलिए बिहार और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने इस विधेयक का सख्त विरोध किया।

ihMh,l esa lèkkj dh njdkj

वर्तमान जर्जर पीडीएस में अकुशलता, भ्रष्टाचार और रिसाव के चलते इसमें सुधार के अनेक सुझाव आते रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक की वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चुप्पी सरकार की इसमें सुधार की नीयत पर प्रष्न चिन्ह लगाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हेतु सुझावों जैसे– फूड स्टैम्प, कुशल प्रबंधन, पारदर्शिता और विस्तृत पहुंच इत्यादि को जैसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अच्छा होता कि सरकार गरीबों को खाद्य कूपन अथवा फूड स्टैम्प जारी करने का प्रावधान बनाती। ऐसे में गरीब सीधे बाजार से इसके माध्यम से अनाज ले पाते। इससे रिसाव भी समाप्त होता और सरकारों को भंडारण समस्याओं से भी निजात मिल पाता। ❑

दैवीय आपदा

उत्तराखंड में प्राकृतिक प्रकोप
विकास बना विनाश का कारण

mÙkjk[kaM dk pkj èkke & dsnkjukFk] cnjhukFk] xaxks=h o ;eukas=h lHkh èkke fodkl ds uke ij izkÑfrd lalkèkuksa ds cMs iSekus ij gq, nksgu ds f'kdkj gks x;s gSA ftudk lekU; voLFkk esa ykus esa irk ugha fdruk o"kZ vkSj yx tk;saA vkSj ns'k Hkj ds yksxksa dh èkkfeZd Hkkouk,a vkxkeh fdrus o"kksaZ rd vkgr gh jgsaxhA xaxk dks iznw"k.k ls cpkus ds fy, ns'k esa gks gYyk gksrk jgrk gS vkSj vHkh rd fdlh Hkh ljdkj us xaxk dks cpkus ds fy, xaxk dks xaxk j{kk vfHk;ku ls ugha tksMk gSA

■ डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

mÙkjk[kaM के 13 वर्ष के जीवन में जिस प्रकार केन्द्र सरकार ने प्रदेशवासियों की आर्थिक प्रगति के लिए आर्थिक सहायता की उससे प्रदेश में भैातिक विकास हुआ और पहाडों का पर्यावरणीय संतुलन बिगड गया। प्रदेश में 16, 17 व 18 जून 2013 तारीखों के दिन बहुत बुरे बीते तथा प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखा कर भारी बरसात तथा बादल फटने की घटना से पहाड़ों पर ढाई से तीन लाख तीर्थयात्री (जिनमें भारी तादाद में मनोरंजन और तीर्थ यात्रियों की थी) वहां नदियों में आयी बाढ़ व भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध होने से पहाड़ों में फंस गये। बाढ़ और भूस्खलन से जो मंजर बना वह अविस्मरणीय के साथ भयानक त्रासदी वाला था। घटना के पांचवें दिन तक 60 से 80 हजार यात्री विभिन्न स्थानों पर भूखे प्यासे व बीमार हालत में फंसे हुए थे। इन यात्रियों में अधिकांश यात्री हवाई यातायात के किराये की सामर्थ्य नहीं रखते थे।

jkT; esa 70 ls vfèkd fctyh ifj;kstukvksa ij dke py jgk gSA lMdsa o Hkou cukus ds fy, ck#n ¼Mk;ukebV½ yxk dj igkMksa esa dEiu mRiUu djds rkMk tk jgk gSA

देश की सेना व प्रदेश की पुलिस मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हुई किसी न किसी प्रकार राहत देने की कोशिश कर रही थी। भौतिक विकास से बिगड़े पर्यावरणीय असंतुलन से गत तीन चार वर्ष से उत्तराखंड में बरसात भारी तबाही मचा रही थी। परन्तु इस वर्ष मानसून आने के पहले ही तपोभूमि अथवा देवभूमि में लगभग प्रलय की भयावही लीला देखी गई। लग रहा था कि भगवान आशुतोष तांडव कर रहे है तथा लग रहा था कि बस यह तांडव वहां मौजूद जिन्दगियों को लील ही जायेगा। जंगल व नदियों के दोहन से कुपित अलकनंदा, भागीरथी व गंगा सभी अपना विकराल रुप दिखा रही थी।

13 वर्ष पूर्व उत्तरप्रदेश को विभाजित कर दुर्गम पहाडी प्रदेश को उत्तराखंड बनाने के पीछे यही उददेश्य था कि यहां के निवासियों को मनीआर्डर संस्कृति से निकाल कर आधुनिक संस्कृति में लाकर उनको बेहतर जीवन स्तर दिया जाए। वहां से लोग अपनी समस्याओं को लेकर लखनऊ व इलाहाबाद नहीं जा पाते थे तो वे लोग देहरादून व नैनीताल जाकर अपनी समस्याओं का निवारण करा सके। इसी

बेहतर जीवन स्तर की लालसा ने देवभूमि व तपोभूमि को आधुनिक पर्यटन स्थल के रुप में परिवर्तित कर दिया और लोग धार्मिक भावना से कम हनीमून मनाने व ऐशो–आराम करने के उद्देश को लेकर ज्यादा जाने लगे जिससे हजारों की संख्या में मोटर, बस, ट्रक व डीजल से चलने वाले वाहन पहाड़ों पर प्रतिदिन पहुंच कर धुएं से पहाड़ी वायु का गला घोंटने लगे। केदारनाथ जहां मुश्किल से एक या दो हजार यात्री एक समय में रुक सकते है वहां 60 हजार यात्री एक समय में पहुंच गये उनके साथ उनके हजारों वाहन भी आ गये। इस सब से क्या वहां के निर्मल पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा? इस दैवीय आपदा में लाखों लोग प्रभावित हुए तथा अनुमान के अनुसार 40–50 हजार लोग मारे गये तथा उनके परिवार की खुशियां बिखर कर रह गई। परिवार वाले अपने परिजनों को दूर दूर तक नदियों में बही लाशों में टटोल रहे है। परिजनों को अपने सगे संबंधी कौन कब कितने साल, महीने अथवा दिनों के बाद खोज खबर मिल सकेगी, कहना मुश्किल हो गया है। जो पहाड़ों पर फंसें हुए है उनको भूख, प्यास व ठंड सता रही है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार केन्द्र की कांग्रेस की सरकार से गुहार कर 1000 करोड़ रुपये अनुदान में पाने में तो सफल रही है अब देखना यह है कि इस रकम में से कितना पैसा सही रूप से पीडितों को मिल सकेगा क्योंकि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों ही आपस में पर्यायवाची शब्द है। उधर विपक्ष भी सियासत करने में पीछे नहीं है। वह राहत देने के लिए स्वयं तो कोई ठोस उपाय नहीं कर रही है अपितु जो कुछ इन परिस्थितियों में हो सकता है उनको लेकर मात्र नुक्ताचीनी ही कर ही है।

सुविधाओं के अभाव में पांच दस रुपये का बिस्कुट का पैकेट सौ रुपये से अधिक का बिक रहा है, 5 हजार रुपये की हैलीकोप्टर की उड़ान के किराये के दो–दो लाख लिये जा रहे है। इस स्थिति में आम आदमी क्या करे।? सेना अपना काम मुस्तैदी से करके पीडितों को सभी प्रकार की सुविधाऐं देने की कोशिश कर रही है। उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर के पूर्व भाजपा विधायक अशोक कंसल भी केदारनाथ में अपने ईष्ट मित्रों व परिवार के साथ इस भयानक त्रासदी में फंस गये थे और बड़ी मुश्किल से पांच दिन बाद वे किसी प्रकार मुजफ्फरनगर पंहुच सके। उनके अनुसार भारी बारिश व बादल फटने से केदारनाथ में बहुत भयानक व दुखद परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। बस भगवान शिव ने उनको किसी प्रकार जीवनदान दिया है।

vc le; vk x;k g] fd tc ge mÙkjk[kM dh èkkfeZd fLFkfr ij iqu% fopkj djsa rFkk igkMksa o iÑfrd lalkèkuksa ds lkFk NsMNkM dk cn djds gfj}kj o _f"kds'k ls Åij ds {ks= dks doy èkkfeZd rhFkZ ;k=k rd gh lhfer djsa ojuk rks mÙkjk[kM dh ;g =klnh ijs ns'k dks fdruk Hk;adj :i fn[kk,] ugh dgk tk ldrk gA

केदारनाथ मंदिर प्रांगण में लाशों के ढेर पडे हुए थे रास्ते में लाशें नदियों में बहती हुई दूर–दूर तक पंहुच गई परन्तु सरकारी आंकड़ा घटना के पांच दिन बाद तक 70 ही शवों का रहा जिस पर आम जन कतई विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। घटना के चश्मदीद बिहार प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा कि 10–15 हजार लोग मारे जा चुके है। बाद में उत्तराखंड की सरकार ने स्वीकार किया कि लगभग 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 200 से ज्यादा पुल व 800 से अधिक सडकें नेस्तनाबूद हो गयी है। निजी होटल, मकान धर्मशालाएं तो हजारो की संख्या में मिट्टी में मिल गई है जिनके नुकसान का अभी आकलन नहीं किया जा सका है।

मौसम विभाग कहता है कि उसने उत्तराखंड की सरकार को पहले से चेता दिया था सरकार लोगों की सलामती के लिए उपाय कर सकती थी। अब भला मौसम विभाग को कौन समझाये कि सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं व सत्ताधीशों में मानवीय संवेदनशीलता निरन्तर क्षीण होती जा रही है। राजनेताओं को तो सत्ता से प्यार होता है। आम जनता से तो वोट लेते समय ही क्षणिक प्यार उमड़ता है। इस हादसे से सरकार का क्या गया? आपदा राहत के नाम पर कुछ करोड़ रुपये और आ गये सरकार का क्या बिगडा, खो गये लोग और थम गये आपसी रिश्ते।

जब तक उत्तराखंड नहीं बना था तब तक उत्तरप्रदेश की सरकार ने जंगल काटने व नदी के किनारे बहुमंजिले इमारतें व होटल बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। जनता टिहरी बांध परियोजना का विरोध कर रही थी तथा नया टिहरी शहर बसा कर समस्या की अनदेखी कर दिया गया। उत्तराखंड को बिजली प्रदेश बनाने के

लिए पहाड़ों को बारुद से तोड़ा जाने लगा। उत्तराखंड में वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया, पर्यटन माफिया आदि सक्रिय हो गये। तीर्थ यात्रियों से धन कमाने के चक्कर में धार्मिक पर्यटन को मनोरंजन पर्यटन के रुप में बदल कर नदियों के किनारे (रिवर व्यू देते हुए) सैंकड़ों की संख्या में बहुमंजिले होटल बना दिये गये जिससे हनीमून जोड़े व ऐशोआराम करने वाले लोग बड़ी संख्या में आकर्षित हो सकें। उत्तराखंड ने अपने जीवन के प्रारम्भ से ही भाजपा व कांगेस की सरकारों ने गैरजिम्मेदाराना हरकतें की है। दोनों के ही कार्यकाल में पहाड़ों व नदियों का बडे पैमाने पर दोहन हुआ। दोनों ही दलों की सरकारों ने अपने अपने कार्यकालों में प्रदेश में बडी संख्या में कारखाने लगाने के लिए निजी डवेलपर्स को आमंत्रित किया। जिससे प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी मात्रा में दोहन हुआ। भागीरथी व अलकनंदा नदी के किनारे पर बहुमंजिले होटल खड़े किये जिनको देशवासियों ने 18 जून 2013 को टीवी पर अपनी आंखों से नदियों में समाते हुए देखा।

सरकार व निजी स्तर पर दोनों को ही कमाई हो रही थी। राज्य में 70 से अधिक बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सडकें व भवन बनाने के लिए बारुद (डायनामइट) लगा कर पहाड़ों में कम्पन उत्पन्न करके तोडा जा रहा है। इस बात को कहने में कोई कौताही नहीं है कि उत्तराखंड के चार धाम – केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री सभी धाम विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर हुए दोहन के शिकार हो गये है जिनको सामान्य अवस्था में लाने में पता नहीं कितने वर्ष और लग जायें और देश भर के लोगों की धार्मिक भावनाएं आगामी कितने वर्षों तक आहत ही रहे। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए देश में हो हल्ला होता रहता है और अभी तक किसी भी सरकार ने गंगा को बचाने के लिए गंगा को गंगा रक्षा अभियान से नहीं जोड़ा है।

अब समय आ गया है कि जब हम उत्तराखंड की धार्मिक स्थिति पर पुनः विचार करें तथा पहाड़ों व प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ को बंद करके हरिद्वार व ऋषिकेश से ऊपर के क्षेत्र को केवल धार्मिक तीर्थ यात्रा तक ही सीमित करे वरना तो उत्तराखंड की यह त्रासदी पूरे देश को कितना भयंकर रुप दिखाये, नहीं कहा जा सकता है। आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर भी जोर देना चाहिए। आपदा को लेकर कुप्रबंधन का खमियाजा कांग्रेस को पूरे देश में भुगतना पड सकता है। पूरे देश से उत्तराखंड में आए सैलानियों व श्रद्धालुओं का अपने परिजनों को खो देने का जो गुस्सा पूरे देश में फैल चुका है और आगामी कई वर्षों तक यह गुस्सा थमने वाला भी नहीं हैं। सभी राज्यों में उत्तराखंड के शासन व प्रशासन की लचरता का संदेश जा रहा है। ❑

%% lwpuk %%

Lons'kh if=dk lekT;okn ds f[kykQ ,d l'kDr vkokt gSA if=dk dks ,sls ykxksa ls ifrfØ;k,¡] fjiksVZ ;k vkys[k dh vis{kk gS tks jk"Vªfgr esa lkprs gSa vkSj ns'k dks LokoyEcu ds fy, dqN djus dh bPNk j[krs gSaA t:jh ugha fd vki i=dkj ;k ys[kd gh gksa] vius vkl ikl ls tqM+h phtksa ds ifr vkidh laosnuk gS vkSj vki 'kCnksa esa mls fy[k ldrs gSa rks gesa vo'; fy[k HkstsaA lkFk gh Lons'kh if=dk esa Nis ys[k vkidks dSls yxrs gSa] D;k vki blesa dqN u, fo"k;ksa dks lekfgr pkgrs gSa Ñi;k gesa vo'; voxr djk,A vkids fopkjksa dks ge izkFkfedrk ds lkFk izdkf'kr djus dk Hkh iz;kl djsaxsA

gekjk irk gS %&

lEiknd

Lons'kh if=dk

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

आपदा की त्रासदी के सबक

ikdfrd vkinkvks dk ckn gekjh v0;oLFkk us =klnh dk ifj.kke dbZ xq.kk c<k fn;k gSA dkQh xkoks dk irk ugha py jgk gSA mudk yksx] mudk lkeku] tkuoj vkfn dgka x,] bldh [kkstchu dh dksbZ fjiksVZ ugha A igkMksa ij gksus ds dkj.k ,d xkao esa ;fn 500 la[;k Hkh eku ysa rks fdruh la[;k gks tk,xhA dsnkjukFk esa djhc 90 èkeZ'kkyk,a gSaA ;s lHkh cg xbZA

■ अवधेश कुमार

fuLlng यह असाधारण और अंदर से तोड़ देने वाली त्रासदी साबित हो रही है। केवल इसलिए नहीं कि प्रकृति की गतिविधियों के कारण नदियों के रौद्र रूप ने उत्तराखंड में प्रलय मचा दिया। यह सच है कि समय पूर्व मानसून नहीं आता, सारी उम्मीदों से करीब 400 गुना ज्यादा बारिश नहीं होती तो संभवतः हमारी अपनी जिंदगी की यह सबसे भयानक त्रासदी घटित ही नहीं होती। तय समय से करीब एक माह पहले पूरे देश में मानूसन सक्रिय हो गया है। सामान्य तौर पर मानसून मध्य जुलाई तक देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। उत्तर–पश्चिम की ओर तेजी से बढे मानसूनी हवा के हिमालय से टकराने के बाद इससे लगे इलाकों में भारी बारिश हुई है, लेकिन यह त्रासदी हमारी विफलताओं से और बढ़ जा रही है।

दो बातों पर गौर कीजिए। एक, अभी तक सरकार की सारी एजेंसियां मिलकर यह भी पता नहीं कर सकीं कि विनाश का विस्तार कहां तक हुआ है? ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी का हवाई दौरा संपन्न हुआ, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी हवाई दौरा किया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। बावजूद इसके यदि हम हय बताने की स्थिति में नहीं रहे कि विनाश कहां से कहां तक गया तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। दो, कितने लोगों की मृत्यु हो गई इसका भी ठीक आकलन कर पाना अभी तक संभव नहीं

हुआ। कम से कम आरंभ के चार दिननों में इसका आकलन हो जाना चाहिए था। इन दो आकलनों के अभाव में पांच दिनों तक यह समझा ही नहीं जा सका कि राहत और बचाव कार्य कितने बड़े पैमाने पर करना होगा और उसमें किस प्रकार की सामग्रियों और सावधानियों की आवश्यकता होगी।

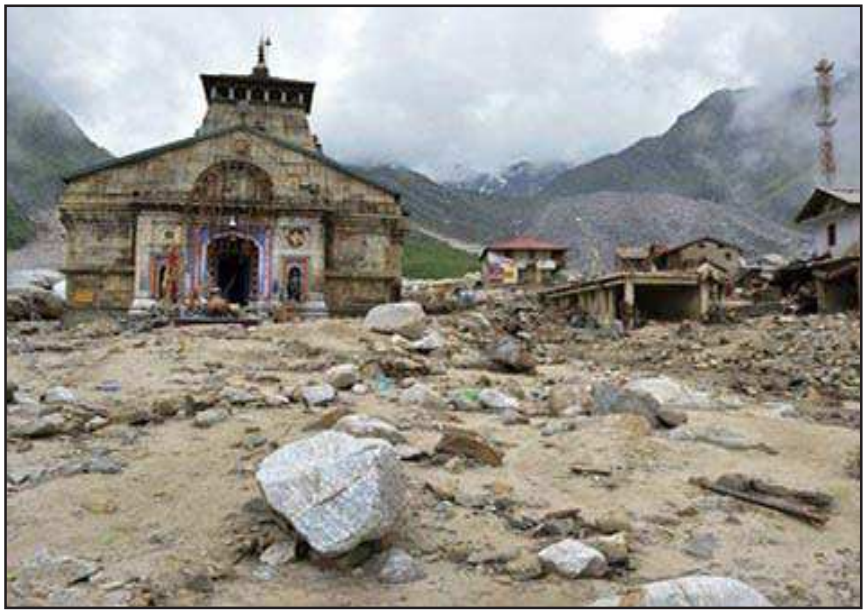

जाहिर है, प्राकृतिक आपदाओं के बाद हमारी अव्यवस्था ने त्रासदी का परिणाम कई गुणा बढ़ा दिया है। काफी गांवों का पता नहीं चल रहा है। उनके लोग, उनके सामान, जानवर आदि कहां गए, इसकी खोजबीन की कोई रिपोर्ट नहीं। पहाडों पर होने के कारण एक गांव में यदि 500 संख्या भी मान लें तो कितनी संख्या हो जएगी। केदारनाथ में करीब 90 धर्मशालाएं हैं। सभी भरीं थी। ये सभी बह गईं। कुछ अन्य पहलुओं के अनुसार अनुमान लगाएं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के 14 किमी के पैदल ट्रैक पर 4700 खच्चर चलते हैं। आपदा वाले दिन सभी बुक थे। एक यात्री और एक खच्चर वाले

****gekjs lkus dk tkou] bfM;u frCcr ckMj Qkslz vkfn dk tkou ftl lkgl vkj èkS;Z dk lkFk jkgr vkj cpko dk vtke ns jgs gS] mudh fuLlng iz'kalk djuh gksxhA****

को जोड़ दें तो संख्या 9400 होती है। पैदल ट्रैक पर 700 डंडी चलती है। एक डंडी को ले जाने के लिए चार लोग के अनुसार संख्या 2800 उनमें बैठे 700 लोगों को मिलाकर 3500 लोग होते हैं। इसी, तरह 500 कंडी संचालित होती है। एक कंडी के साथ दो लोग होते हैं और एक यात्री बैठता है। इनकी संख्या हुई 1500। केदारनाथ से लेकर गौरीकुंड तक 250 होटल हैं। एक होटल में कम से कम चार कर्मचारी हो जाते हैं। केदारनाथ के होटलों में 6000 के तथा गौरीकुंड के होटलों में 8000 के ठहरने की व्यवस्था है। सभी होटल भरे थे। अनुमान है कि करीब एक लाख पर्यटक राजधानी होते हुए उत्तराखंड गए थे। दिल्ली से विभिन्न टूर एंड ट्रैवल्स की 40 से अधिक बसों से गए पर्यटकों की सूचना नहीं है। प्रत्येक बस में करीब 20 से 25 पर्यटक सवार थे।

बाहर आते लोगों की आपबीती सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उत्तराखंड से लौटकर कहा कि केदारनाथ में चारों ओर लाशें बिछी हुई थीं, लेकिन उन्हें उठाने वाला भी कोई नहीं। बचे हुए लोग लाशें लांघ कर निकल रहे हैं। चौबेने कहा, 'मैं चार रातों तक केदारनाथ में फंसा रहा। मैंने लाशों पर रातें बिताईं। 800 से ज्यादा लोग मेरे साथ मंदिर में थे। कई तो मेरी आंखों के सामने मर गए। मंदिर के अंदर लाशें तैर रही थीं। चौबे के परिवार के पांच लोग लापता हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। कोई पति–पत्नी एक–दूसरे का हाथ पकड़ कर बचने के का प्रयास कर रहे थे। पानी का रेला आया और एक को बहा ले गया। दूसरा बिलखता देखता रहा। कोई मां अपने बच्चे को गोद में लिए ही बह गई तो किसी का बच्चा बच गया और मां बह गई तो कोई बच्चा मां की गोद में ही मर गया। कितने परिवार खत्म हो गए। बारिश थमने के तुरंत बाद राहत न मिलने से काफी संख्या मं लोग मारे गए।

हमारे सेना के जवान, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स आदि के जवान जिस साहस और धैर्य के साथ राहत और बचाव को अंजाम दे रहे हैं, उनकी निस्संदेह प्रशंसा करनी होगी। किंतु राजनीतिक नेतृत्व की नासमझी और समय से सक्रिय न होने के कारण इसमें काफी देर हुई। अगर बारिश रुकते–रुकते केंद्र और राज्य सरकार के सारे संबंधित विभाग युद्ध स्तर पर आवश्यक साजो सामान के साथ कूद गए होते तो ज्यादातर लोग बचाए जा सकते थे। लोग रात भर ठंड में सिकुड़ते–मरते रहे। हमारे संबंधित विभागों को यह मालूम ही नहीं था कि कितने बड़े पैमाने पर बचाव और राहत चलाना होगा। 18 जून को 10 हैलीकॉप्टरों ने राहत एवं बचाव कार्य में हिस्सा लिया। धीरे–धीरे विनाश का विकराल रूप दिखने लगा तो फिर भागदौड़ आरंभ हुई और 20 जून को 22 से 25 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे।

v/kk/kqa/k [kuu vkSj tyfo|qr ifj;kstukvksa dk dkj.k gqvk fouk'k

& fnus'k jkor] lkekftd dk;ZdrkZ] xzko % dkukjk] ftyk pekyh] uUn iz;kx

उत्तराखंड में जिस विनाशलीला को आज देश देख रहा है, उसका मुख्य कारण प्रकृति के साथ खिलवाड है। राज्य में अनगिनत विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई है और बांध बनाने के लिए पहाड़ों के अंदर सुरंग खोदकर नदियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अगर सभी योजनाओं पर काम पूरा हो गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब उत्तराखंड में नदियों के दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। इन सबसे पैदा होने वाले संकट से मनुष्य के अलावा पशु–पक्षियों तक का जीवन संकट में आ जाएगा।

आज भागीरथी का प्रवाह गंगोत्री से हरिद्वार तक आते–आते लगभग सिमटने लगा है। गंगोत्री से करीब 130 किलोमीटर दूर धरासू तक नदी को सुरंग में डालने से धरातल पर उसका अस्तित्व खत्म सा हो गया है। यहां 16 जलविद्युत परियोजनाओं की वजह से भागीरथी को सुरंगों में डाला जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में सुरंगों के कारण नदियों की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर अगर नदियों को सुरंगों में डाला गया तो जहां नदी बहा करती थी वहां केवल नदी के निशान ही बचेंगे।

इसके अलावा अंधाधुंध खनन और सुरंग बनाने के लिए की गए विस्फोटों से भी हिमालय कमजोर हो रहा है। देखा जाए तो आप पूरा उत्तराखण्ड में खनन माफिया और राज्य सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है यह विनाश लीला। अब समय आ गया है कि हिमालय पर्यावरण पर जितनी भी जल विद्युत परियोजना और बांध बनाने की प्रक्रिया तुरंत बन्द की जाए ताकि हिमालय में फिर से कोई बड़ी आपदा न हो। ❑

20 जून को गृहमंत्री ने रक्षा मंत्री से और हेलीकॉप्टर और कई हजार जवान देने का अनुरोध किया एवं फिर 55 हेलीकॉप्टर और कई हजार जवान राहत और बचाव में लगाए गए।

अगर बचे लोगों की आपबीती सुनें तो कम से कम तीन दिनों तक कपड़े, दवा या खाने का कोई इंतजाम नहीं था। लोग राहत दल से यह उम्मीद कर रहे थे कि उनके पास कुछ खाने, पीने, चादर, कपडे, दवाइयां होंगी, पर वे तो खाली हाथ उन्हें निकालने आए थे। 20 जून को केदारनाथ वन्यजीव विहार के जंगल में 25 लोगों की ऐसी दर्दनाक मौत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की आंखों के सामने हुई। जवान बचाव करने के लिए जंगल में पहुंचे हुए थे, लेकिन इनके पास पिलाने के लिए पानी, कुछ भोजन और गरम चादर तक नहीं थे। इसलिए बचाव के दौरान ही इन लोगों की मौत हो गई। आरंभ में लोगों को सुरक्षित बाहर लाने गए दल ने यह सोचा ही नहीं कि उनके पास कुछ गरम कपड़े, पीने का पानी और खाना भी होना चाहिए। जरा सोचिए, यह प्रकृति की मार है या हमारी? प्रशासन को यह भी कल्पना नहीं थी कि हम जिन्हें बाहर निकालने जा रहे हैं, उनके मृत परिजनों के अगर शव होंगे तो उनका क्या किया जाएगा।

nonr cudj vk, lfud

अगर सेना न होती तो इस भीषण आपदा में कौन किसकी सहायता कर पाता? टेलीविजन चैनलों पर आकर मुंह चमकाते नेता–सरकारी अधिकारी इत्यादि केवल आंकड़ों की बाजीगरी करते रहे वही दूसरी तरफ उत्तराखण्ड सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ऐसे में भारतीय सेना और वायुसेना के हैलीकाप्टरों ने तीर्थ–यात्री और गांवों की जो मदद की उससे सेना की छवि एक – देवदूत बनकर उभरी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, अगस्तमुनि, तिलबाड़ा, जंगल चट्टी हेमकुंड साहब, गोविंदधाम, गोविंदघाट और हनुमान चट्टी के तंग पहाड़ियों और छोटी–छोटी घाटियों से बहुत नीची उड़ान भरते हुए जांबाजी और सेवाभाव से सैनिकों ने जिस तरह तीर्थयात्रियों को निकाला सचमुच प्रशंसनीय काम था। सैनिकों के अफसरों की केवल एक ही चिंता थी कि मौसम खराब होने से पहले प्रकृति आपदा में फंसे लोगों को शीघ्र से शीघ्र निकाला जाए। यह काम केवल सेना के जवान ही कर सकते थे। सेना के जवानों ने न केवल हैलीकाप्टर की उड़ान संचालित कर रहे थे बल्कि लोगों को लाइन में लगाना, उनको नियंत्रित रखना, उनके बीच टोकन तक बांटना, ताकि लोग रात–रात भर खुले में हैलीकाप्टर के इंतजार में भीगते न रहें, यह सब भी वही कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सेना के जवानों ने बुजुर्ग लोग, असहाय लोग, थके–मांदे लोगों को हैलीकाप्टर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना साथ ही उनका सामान भी कंधों पर ढोया। और तो और जो बेहद लाचार थे, चलने में सक्षम नहीं थे, उन्हें भी कई–कई किलोमीटर तक कंधों पर ढोकर सुरक्षित नीचे तक पहुंचाया। इसलिए आपदा पीड़ितों की जुबान पर एक ही बात थी सैनिक हमारे लिए देवदूत हैं और सरकार नाकारा है, अब तो हमें सिर्फ सैनिकों का सहारा है।

ये सारे तथ्य हमें एक ओर स्तब्ध और द्रवित करते हैं कि उसके साथ क्षोभ, छटपटाहट और तिलमिलाहट पैदा कर रहे हैं। हमने विकास की कामना से हिमालय की वादियों में बसे इस प्रदेश के संतुलन को नष्ट कर स्वयं विनाश के लिए व्यापक आधार बना दिया और यह भी कल्पना नहीं कि अगर कभी अनर्थ हुआ तो उनसे निपटेंगे कैसे। साफ है कि तथाकथित विकास की इस चकाचौंध में हम इतने खो गए हैं कि इसके अन्य अवश्यंभावी भयावह पहलुओं की ओर समग्रता से सोचने की जहमत ही नहीं उठाते। अमरीका, यूरोप और जापान आदि ने यदि प्रकृति को रौंद्रा तो विनाश से निपटने की मानवीय, यांत्रिक व्यवस्थाएं भी कीं। इसलिए हर अनर्थकारी घटना के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है। दूसरी ओर हम लंबे समय तक पीड़ित और मजबूर लोगों की नियति के हवाले छोड़ देते हैं। ❑

dnkjnkukFk efnj dk cpuk peRdkj l de ugh

जल प्रलय के कारण केदारनाथ में बनी दुकानें, धर्मशालाएं और पैदल मार्ग सब कुछ तबाह हो गया लेकिन प्राचीन केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रहना भी एक चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। चमत्कार यह हुआ कि जब प्रलय आयी तो उसके साथ एक बड़ी चट्टान भी बहकर आई और मंदिर से कुछ दूरी पर जम गई। जिसके कारण जलधारा दो हिस्से में बंट गई और मंदिर तक तेज बहाव नहीं पहुंच पाया, इस प्रकारण केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। वही पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर प्राचीन स्थापत्य के कारण बच पाया है। लेकिन जो कुछ भी हो केदारनाथ मंदिर का जलप्रलय में सुरक्षित रहना यह भी किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है।

विकास की विभीषिका

ckny QVuk lkekU; ckr g] ijrq fxjs ikuh dks xg.k djus dh èkjrh dh 'kfä dks geus tyfo|qr ifj;kstukvksa dk cuku ds fy, fd, tk jgs foLQksVksa ls detksj cuk fn;k gSA ,sls gh çHkko lM+dksa dks cukus ds fy, fd, x, foLQksVksa vkSj xSjdkuwuh [kuu dk gksrk gSA unh ds ikV ij fd, tk jgs vfrØe.k ls 0;fä viu dks ck<+ ds eqg esa Mkyrk gSA

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

gky में उत्तराखंड में आई विभीषिका का प्रत्यक्ष कारण ग्लोबल वार्मिंग दिखता है। धरती का तापमान बढ़ने से बरसात तेज और कम समय में हो रही है। भीषण बरसात और सूखे के दौरे पड़ रहे हैं। वायुमंडल की विशेष परिस्थिति में बादल फटते हैं। सामान्य परिस्थिति में हवा पानी की बूंदों को लेकर ऊपर उठती रहती है। छोटी बूंदें बड़ी होती जाती हैं। तापमान कम होता है तो ये बूंदें बर्फ बन जाती हैं और ओले का रूप धारण कर लेती हैं। विशेष परिस्थितियों में हवा ऊपर नहीं उठ पाती है, परंतु पानी की बूंदें बड़ी होती जाती हैं। ये बड़ी बूंदें एकदम से गिर पड़ती हैं, जिसे बादल फटना कहा जाता है।

गिरने वाले इस पानी को यदि पहाड़ सहन कर लेता है तो विशेष नुकसान नहीं होता है। पहाड़ कमजोर हो तो वही पानी विभीषिका का रूप धारण कर लेता है। बड़ी मात्रा में पेड़ लगे हों तो पानी उनकी जड़ों के सहारे पहाड़ के अंदर तालाबों में समा जाता है, जिन्हें एक्वीफर कहते हैं। पेड़ कमजोर हों तो वही पानी सीधी धारा बनाकर नीचे गिरता है और अपने साथ पेड़ों और पत्थरों को लाकर नदी में डाल देता है। तब उफनती नदी अपने साथ पेड़ों और पत्थरों को लेकर बहती है। इनकी टक्कर से मकान और पुल ध्वस्त हो जाते हैं, जैसा कि हाल में हुआ है।

केदारनाथ के नीचे फाटा व्यूंग और सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। इनमें लगभग 30 किलोमीटर की सुरंग खोदी जा रही है। भारी मात्रा में डायनामाइट का प्रयोग किया जा रहा है। इन विस्फोटों से पहाड़ के एक्वीफर फूट रहे हैं और जमा पानी रिस कर सुरंग के रास्ते निकल रहा है। पहाड़ के जल स्रोत सूख रहे हैं। पेड़ों को पानी नहीं मिल रहा है और वे कमजोर हो रहे हैं। धमाकों से पहाड़ कमजोर और जर्जर हो रहे हैं। फलस्वरूप पानी बरसने से चट्टानें धसक रही हैं तथा पत्थर नीचे आ रहे हैं। मैने सूचना के अधिकार के अंतर्गत डाइरेक्टर जनरल आफ माइन सेफ्टी से पूछा कि विस्फोट की मात्रा के निर्धारण संबंधी फाइल मुझे उपलब्ध कराई जाए। उत्तर दिया गया कि फाइल गुम हो

dsnkjukFk ds uhps QkVk 0;wax vkSj flaxksyh HkVokjh ty fo|qr ifj;kstuk,a cukbZ tk jgh gSA buesa yxHkx 30 fdyksehVj dh lqjax [kksnh tk jgh gSA Hkkjh ek=k esa Mk;ukekbV dk ç;ksx fd;k tk jgk gSA bu foLQksVksa ls igkM+ ds ,DohQj QwV jgs gSa vkSj tek ikuh fjl dj lqjax ds jkLrs fudy jgk gSA igkM+ ds ty lzksr lw[k jgs gSaA iM+ksa dks ikuh ugha fey jgk gS vkSj os detksj gks jgs gSaA èkekdksa ls igkM+ detksj vkSj ttZj gks jgs gSaA QyLo:i ikuh cjlus ls pêkusa èkld jgh gSa rFkk iRFkj uhps vk jgs gSaA

गई है। इससे ज्ञात होता है कि कंपनियां विस्फोटों पर परदा डालना चाहती हैं। वर्तमान विभीषिका में श्रीनगर परियोजना का विशेष योगदान रहा है। कंपनी ने भारी मात्रा में मिट्टी को नदी के किनारे डाल दिया था। जलस्तर बढ़ने पर यह मिट्टी नदी के साथ बहकर घरों में घुस गई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हो गई। राजमार्ग सात दिनों से बंद है।

सारांश है कि बादल फटना सामान्य बात है, परंतु गिरे पानी को ग्रहण करने की धरती की शक्ति को हमने जलविद्युत परियोजनाओं को बनाने के लिए किए जा रहे विस्फोटों से कमजोर बना दिया है। ऐसा ही प्रभाव सड़कों को बनाने के लिए किए गए विस्फोटों और गैरकानूनी खनन का होता है। नदी के पाट पर किए जा रहे अतिक्रमण से व्यक्ति अपने को बाढ़ के मुंह में डालता है।

जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का लाभ शहरी उपभोक्ताओं को होता है। उत्तराखंड के पास अपनी जरूरत भर बिजली उपलब्ध है, लेकिन राजस्व कमाने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक नदी के प्रत्येक इंच के बहाव पर जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रयास कर रही है। इन परियोजनाओं से राज्य को 12 प्रतिशत बिजली फ्री मिलती है। इसे बेचकर सरकार राजस्व कमाती है। इस राजस्व में आधा सरकारी कर्मियों के वेतन को जाता है। शेष में बड़ा हिस्सा अन्य प्रशासनिक खर्चो में जाता है, जैसे गाड़ी इत्यादि में। बची रकम विकास कार्यों में खर्च की जाती है। इसमें 20 से 50 प्रतिशत घूस में जाता है। आम आदमी को राजस्व का केवल 20–25 प्रतिशत ही मिलता है, लेकिन परियोजना के 100 प्रतिशत दुष्परिणाम को आम आदमी झेलता है। उसकी बालू–मछली से होने वाली आय बंद हो जाती है। परियोजना में उत्पन्न मच्छरों से आम अदमी की मृत्यु होती है। विस्फोटों से आई विभीषिका का ठीकरा भी आम आदमी के सिर ही फूटता है।

इसी प्रकार का प्रभाव दूसरे विकास कार्यों का होता है। अंधाधुंध खनन से लाभ खनन माफिया को होता है। खनिज का उपयोग मुख्य रूप से अमीरों की इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। सरकार को अवैध खनन से राजस्व कम और सरकारी कर्मियों को घूस ज्यादा मिलती है। नदी के पाट में अतिक्रमण का प्रभाव भी ऐसा ही है। अतिक्रमण प्रभावी वर्ग ही करता है। अमीर को सस्ती भूमि हासिल हो जाती है। सरकार को रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं मिलता है। हां घूस भरपूर मिलती है। इनके कार्यों के विपरीत सड़क निर्माण का आम आदमी पर सुप्रभाव पड़ता है। उसके लिए आवागमन सुगम हो जाता है। कॉलेज, अस्पताल और सॉफ्टवेयर पार्क बनाने का आधार बनता है। इनसे दीर्घकालीन और उच्चकोटि के रोजगार स्थापित होते हैं, जैसे लेक्चरर या साइंटिस्ट के। समग्र दृष्टि से देखने पर विभीषिका के कारणों में मात्र सड़क बनाना ही लाभप्रद दिखता है। सड़क निर्माण से आपदा में वृद्धि न हो, इसके लिए डायनामाइट का उपयोग अपरिहार्य स्थिति में ही किया जाए। छेनी और सब्बल से ही पहाड़ काटना चाहिए। हां इससे निर्माण कार्य धीमी गति से होगा, पर पहाड़ जर्जर होने से बच जाएंगे।

अवैध खनन, अतिक्रमण और जल विद्युत परियोजनाएं इस विभीषिका के कारण हैं। इन परियोजनाओं में घूस वसूलने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। जानकार बताते हैं कि जल विद्युत परियोजनाओं का अनुबंध दस्तखत करने का मंत्रीगण एक करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की घूस लेते हैं। उत्तराखण्ड में 40,000 मेगावाट की संभावना को देखते हुए घूस की इस विशाल राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। इन कार्यों के माध्यम से राज्य सरकार गरीब पर आपदा डालकर अमीर को लाभ पहुंचा रही है और इस पाप में अपना हिस्सा

vydunk ij fctyh ikt DV l vkbl rckgh

& pMh i zl kn HkVV ¼i ;kobj.kfon½

पर्यावरणविद और पद्मभूषण चंडी प्रसाद भट्ट के अनुसार मध्य हिमालय का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अलकनंदा पर बनी विद्युत परियोजनाएं 'ब्लू प्रिंट फौर डिजास्टर' साबित हो रही है। विद्युत परियोजनाओं वाले क्षेत्र खड़ी तेज डाल वाले बर्फ से ढके पहाड़ों में घिरे हैं, जहां अब बडे पैमाने पर हिमखण्डों और भूमि का स्खलन हो रहा है। उन्होंने विष्णुप्रयाग के लामबगड बैराज नष्ट होने को हिमालय के साथ छेड़छाड़ का नतीजा बताते हुए कहा कि इस बैराज के ध्वस्त होने के बाद अलकनंदा में आई बाढ़ से गोविन्दघाट के कई भवन ध्वस्त हो गए। परियोजना का बैराज वाला स्थल संवेदनशील है, इसे कभी भी नीति नियंताओं ने ध्यान में नहीं रखा। बैराज और उसके आसपास के निर्माण को नष्ट तो होना ही था, लेकिन लामबगड़, पांडुकेश्वर और गोविन्दघाट में हुआ करोड़ों का नुकसान बताता है कि दोष किसी और का रहा और खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा। ❑

बटोर रही है।

vkink dk dkj.k

उत्तराखण्ड में आयी विभीषिका में विद्युत परियोजनाओं की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी बहती है। फाटा व्यूंग और सिंगोली भटवाड़ी नाम से केदारनाथ के नीचे इस नदी पर दो विद्युत परियोजनायें बन रही हैं। इन परियोजनाओं में प्रत्येक में 15–20 किमी की सुरंगे पहाड़ में खोदी जा रही है। इन सुरंगों को बनाने में भारी मात्रा में डायनामाइट का प्रयोग किया जा गया है। इनके धमाकों से पहाड़ दरक गये हैं और उनपर उग रहे पेड़ कमजोर हो गये हैं।

केदारनाथ से लगभग 100 किमी नीचे श्रीनगर जल विद्युत परियोजना बन रही है। इस परियोजना में टिहरी बांध की तरह लगभग 30 किमी की झील बनी है। इन सभी परियोजनाओं के कारण स्थानीय पर्यावरण में भारी बदलाव हो रहा है।

अलकनंदा में माहसीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किन्तु अंडा देने के लिये यह उपर जाती है। बांध की अड़चन के कारण यह ऊपर अपने प्रजनन क्षेत्र तक नहीं जा पायेगी। मछलियों, केंचुओं तथा कछुओं का भोजन 'गाद' होती है। यह बांध की झील में जमा हो जायेगी। ये जीव जन्तु भूखे रह जायेंगे। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के निर्माण में भारी मात्रा में जंगल काटे गये हैं या फिर झील में डुबाये गये हैं। इन मानवीय कृत्यों के कारण स्थानीय वायुमंडल में बदलाव आ रहा है। मछलियों का संबन्ध छोटे जलीय जंतुओं से होता है जिन्हें ये खाती हैं। इन जन्तुओं का सम्बन्ध नदी किनारे उग रही वनस्पतियों से होता है और वनस्पतियों का वायुमंडल से। इस प्रकार मछलियों के मरने से वायुमंडल प्रभावित होता है। इन परियोजनाओं को बनाने के लिये उपयोग किये गये डायनामाइट से पहाड़ हिल जाते हैं और जल स्त्रोत सूख जाते हैं। इससे जंगल कमजोर होते हैं। परियोजनाओं को बनाते समय सीधे भी जंगल को काटा और डुबाया जाता है। जंगलों के कमजोर होने से वायुमंडल सीधे प्रभावित होता है। ये वायुमंडल में कार्बनडाइ आक्साइड की मात्रा को प्रभावित करते हैं। झील बनने से वायुमंडल सीधे प्रभावित होता है। झील से वायु का वाष्पीकरण अधिक होता है। संभव है कि वाष्प की इस अधिकता के कारण ही उस क्षेत्र में बादल अधिक फटे हों।

mÙkjk[k.M esa ijEijk gS fd nsoh&nsork fdlh O;fDr ij vorfjr gksdj viuh ckr dgrs gSA o"kZ 2009 esa nsoh us dk;Znk;h dEiuh ds vfèkdkfj;ksa ds lkeus izR;{k dgk Fkk fd os viuk LFkku ls mBuk ugha pkgrh gSA 15 twu dks mudh izfrek dks mBkus dk iz;kl djrs le; mUgksaus iqu% dgk fd ^^eq>s er mBkvks ugha rks foMky ykÅaxhA**

दूसरा पक्ष राष्ट्र की उर्जा सुरक्षा का है। सरकार की पालिसी है कि ऊर्जा की सम्पूर्ण भूख को पूरा किया जाये जो कि सम्भव नहीं है चूंकि ऐसी भूख कभी पूरी होती ही नहीं। वर्तमान में उर्जा की खपत घरेलू क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। बड़े शहरों की कोठियों में 4 व्यक्तियों के परिवार के लिये 25,000 रू0 प्रति माह का बिजली का बिल सामान्य हो गया है। एयर कंडीशनर इत्यादि चौबीस घंटे चलते हैं। इस खपत से आर्थिक विकास नहीं होता है। विकास मुख्यतः सर्विस सेक्टर से हो रहा है। उर्जा की खपत को हम आयातित तेल, कोयले तथा यूरेनियम पर निर्भर होते जा रहे हैं। यदि पश्चिम एशिया के देशों ने हमें तेल देना बन्द कर दिया तो हम 15 दिन में ही घुटने टेक देंगे। अतः विलासिता के लिये उर्जा की खपत कम करनी चाहिये। जल विद्युत के लिये नदियों को नष्ट करके हम उर्जा की इस अनन्त भूख की पूर्ति नहीं कर पायेंगे।

तीसरा पक्ष अंर्तराष्ट्रीय है। विकसित देशों का दबाव है कि हम थर्मल उर्जा का उत्पादन कम करें क्योंकि इसमें हुये कार्बन उत्सर्जन से वे प्रभावित होते हैं। वे चाहते हैं कि हम हाइड्रोपावर ज्यादा बनायें क्योंकि वे इसके दुष्परिणामों से बचे रहते हैं। हमें इस सलाह से दोहरा नुकसान है। दूसरे देशों द्वारा बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से हम प्रभावित होंगे और उनको बचाने के चक्कर में हम अपनी नदियों को नष्ट कर देंगे और हमारा पर्यावरण दुबारा दूषित होगा।

चौथा पक्ष जनहित का है। धर्म कहता है कि राजा को गरीब का विशेष ध्यान देना चाहिये। यही गांधीजी का सपना था। परन्तु हाइड्रोपावर की चाल इसके विपरीत है। इन परियोजनाओं के दुष्परिणाम गरीब पर पड़ते हैं। वे नदी से मिलने वाली बालू और मछली से वंचित हो जाते हैं। उनके जल स्रोत सूखते हैं। खेती प्रभावित होती है। झील में पनपने वाले मच्छर और झील से निकलने वाली मीथेन गैस से उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। जमीन धसकने से उसके मकान टूटते हैं। दूसरी ओर बिजली महानगरों और राजधानी के

लोगों को आराम देने के लिये चली जाती है। इस प्रकार परियोजना के माध्यम से गरीब के संसाधन छीन कर अमीरों को पहुंचाये जा रहे हैं। पर्यावरण, उर्जा सुरक्षा, अर्न्तराष्ट्रीय कूटनीति एवं गरीब पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा जाये तो ये परियोजनाये अधर्म की मूर्तियां हैं। ये परियोजनायें आर्थिक विकास में भी सहायक नहीं हैं। दूसरे तमाम दुष्प्रभावों का खामियाजा समाज भुगतता है जैसे मछली, मच्छर, बालू, उर्जा सुरक्षा इत्यादि का। इन तमाम दुष्प्रभावों का आर्थिक आकलन कर लिया जाये तो सिद्ध हो जायेगा कि ये परियोजनायें आर्थिक विकास के लिये भी हानिकारक हैं।

वर्तमान विभीषिका में धारी देवी प्रतिमा के उठाने का भी योगदान हो सकता है। श्रीनगर परियोजना की झील के डूब में धारी देवी मंदिर आ रहा है। इस मंदिर में वैष्णों देवी की तरह शिला की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्यजी ने यहां तपस्या की थी। समयक्रम में शिला के सामने एक मूर्ति स्थापित कर दी गई है। परियोजना की कार्यदायी कम्पनी ने 15 जून को मूर्ति को उठाकर उसी स्थान पर खम्भों पर स्थापित कर दिया और मूल शिला को झील में जलमग्न कर दिया। धारी देवी को डुबाना उसी तरह हुआ कि हेमकुझड साहब अथवा मक्का को हाइड्रोपावर पावर के लिये जल में विलीन करना।

उत्तराखण्ड में परम्परा है कि देवी–देवता किसी व्यक्ति पर अवतरित होकर अपनी बात कहते हैं। वर्ष 2009 में देवी ने कार्यदायी कम्पनी के अधिकारियों के सामने प्रत्यक्ष कहा था कि वे अपने स्थान से उठना नहीं चाहती हैं। 15 जून को उनकी प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते समय उन्होंने पुनः कहा कि ''मुझे मत उठाओं नहीं तो विडाल लाऊंगी।'' मूर्ति को उठाने के चन्द घन्टों के बाद बादल फटना शुरू हो गया। इन तमाम दुष्प्रभावों को देखते हुये हिमालयी पर्वतों पर जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने की पालिसी पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिये।❑

%% lnL;rk lcèkh lpuk %%

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

lnL;rk 'kqYd fuEu izdkj gS %&

Lons'kh if=dk	okf"kZd	vkthou
fgUnh	150 रुपए	1500/– रुपए
vaxzsth	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

पता : **Lons'kh if=dk dk;kZy;] ^èkeZ{ks=* f'ko 'kfDr efUnj] lSDVj&8] jkeÑ".kiqje] ubZ fnYyh&22**

समाचार परिक्रमा

दिल्ली की सड़कों पर विदेशी बसें दौड़ेंगी

tgk अर्थव्यवस्था की सुस्ती के कारण और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए से उद्योग जगत परेशान है। वही दूसरी तरह दिल्ली वालों को बेहतर बसें उपलब्ध कराने के नाम पर विदेशी गाड़ियां सड़कों पर उतारने के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री बैचेन है। ये गाड़ियां पौलैण्ड, स्वीडन व चीन से आएगी। इन देशों की वाताकूलित व सामान्य बसों का ट्रायल किया जाएगा। यह निर्णय दिल्ली परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी की अध्यक्षता वाली बैठक में किया गया है। इन बसों को जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत खरीदा जाएगा। ❑

दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी मिली

vrj मंत्रालयी निकाय दूरसंचार आयोग ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को मौजूदा 74 प्रतिशत से बढाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है। आयोग ने एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। इसमें से 49 प्रतिशत निवेश स्वतः स्वीकृति (आटोमेटिक रूट) किया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक स्तर के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी जरूरी होगी। दूरसंचार विभाग इस बारे में एक विस्तृत नोट औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को भेजेगा जो प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजेगा। इस फैसले पर कार्यान्वयन तो कैबिनेट मंजूरी के बाद ही होगा। इस क्षेत्र में फिलहाल 74 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी है जिसमें से 49 प्रतिशत स्वतः किया जा सकता है जबकि बाकी के लिए एफआईपीबी की मंजूरी की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढाने के पीछे मंशा दूरसंचार उद्योग को नया निवेश हासिल करने में मदद करना है ताकि उसे वित्तीय बोझ घटाने में मदद मिले। ❑

फार्मा क्षेत्र में एफडीआई के 7 प्रस्ताव मंजूरी

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने भारतीय फार्मास्युटिकल्स कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 7 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जबकि स्वामित्व नियंत्रण के मुद्दे को लेकर 3 अन्य पर फैसला टाल दिया। बोर्ड की बैठक के वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुमारएफआईपीबी ने सभी आवेदनों पर विचार किया और पात्रता के हिसाब से फैसला किया। हमने 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी और 3 अन्य पर फैसला टाल दिया। आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अगुवाई वाले विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने कुल 30 एफडीआई प्रस्तावों पर विचार किया। इनमें सात फार्मा क्षेत्र से संबंधित हैं। एफआईपीबी की बैठक में जिन प्रस्तावों पर विचार हुआ उनमें सिंगापुर ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन प्राइवेट लिमिटेड, अमेरिका की माइलैन इंक, मॉरीशस की कैसलटन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मुंबई की फेरिंग थेरापेटिक्स और हैदराबाद की वेदांत लाइफ साइंसेज शामिल हैं। फिलहाल देश में फार्मा क्षेत्र में नई परियोजनाओं में स्वतः मंजूर मार्ग से शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है, जबकि मौजूदा फार्मा कंपनियों में एफडीआई की अनुमति सिर्फ एफआईपीबी की मंजूरी के बाद मिलती है। केन्द्र सरकार जल्द मौजूदा दवा कंपनियों के लिए एफडीआई नीति को अंतिम रूप देने वाली है।❑

62 रुपए प्रति डॉलर तक जा सकता है रुपया

fiNy कुछ माह में करीब 10 प्रतिशत नीचे आने वाले रुपए में आगामी तीन माह में और गिरावट आने की आशंका है। क्रेडिट सुईस ने कहा कि अगले तीन माह में रुपए 61.50 प्रति डॉलर के स्तर पर नीचे आ सकता है। साथ ही अगले 12 महीने में रुपया 62 रुपए प्रति डॉलर तक जा सकता है। क्रेडिट सुईस की रिपोर्ट के अनुसार यदि रुपए में यही रुख जारी रहता है तो रिजर्व बैंक द्वारा 30 जुलाई को मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद शून्य है। लेकिन यदि रुपया इसी तरह गिरता रहा तो रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ❑

रुपए के गिरने से उपभोक्ता मुश्किल में

vejhdh डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा रुपया अब देश की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ आम उपभोक्ता के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के जोखिम लेने की क्षमता और तरलता में आई कमी ने भारतीय रुपए को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही फेडरल बैंक द्वारा प्रोत्साहन पैकेज की राशि को कम करने की घोषणा का भी डॉलर की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। डॉलर की मांग और आपूर्ति बिगड़ने की वजह से रुपया कमजोर हो गया है। इसका असर भारत के बाहर भी कई देशों पर पड़ा है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता को अब बढ़ते पेट्रौल, डीजल और महंगी बिजली और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ❑

खतरे में भारत की साख

of'od रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भारत की साख घटने की वजह बन सकती है। मूडीज की निवेश सेवा विश्लेषक अत्सी सेठ ने कहा कि रुपए में कमजोरी वृहत–आर्थिक चुनौतियों को जाहिर करती है जिससे देश की साख पर असर होगा। रुपया अब 59.93 के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। मूडीज ने रुपए में गिरावट के लिए चालू खाते के उच्च घाटे को जिम्मेदार ठहराया है।❑

निर्यात में तेजी से ही रुपया होगा मजबूत

Hkkjrh; रिजर्व बैंक के उपगवर्नर के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि रुपए में आ रही गिरावट को थामने के लिए निर्यात में तेजी लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आरबीआई के पास रुपए में तेजी लाने के लिए कोई रामबाण दवा नहीं है। उसके पास सीमित विकल्प है जिस पर वह लगातार काम कर रहा है ऐसे में निर्यात में बढ़ोतरी और विनिर्माण गतिविधियों में तेजी ही रुपए को सुधार सकती है। अर्थव्यवस्था के साथ कोई परेशानी नहीं है बस जरूरत है इसे और मजबूत करने की। ❑

चीन ने की फिर घुसपैठ

phu अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने फिर से लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसकर तोड़फोड़ और हिन्दी में जगह खाली करने की धमकी भी दी है। लेकिन केन्द्र सरकार अभी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। देखा जाए सरकार की चुप्पी एक प्रकार से देश की लिए ठीक नहीं है। ❑

एफडीआई नियमों में बदलाव की कोशिश कर रही है केन्द्र सरकार

fon'kh कंपनियों को अपने देश में लाने के लिए उतावली केन्द्र सरकार अब मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत के बावजूद विदेशी कंपनियों की बेरुखी देख सरकार अब इस नीति के कुछ नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है। सरकार विदेशी कंपनियों की मांग पर स्टोर खोलने के लिए शहरों की आबादी के मानक और स्थानीय स्तर पर खरीद के नियमों में कुछ रियायत की संभावनाएं तलाश रही है। गत दिनों वालमार्ट, कारफू जैसी विदेशी मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनियों के साथ हुई बैठक हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियां चाहती हैं कि भारत में कारोबार को व्यावहारिक बनाने के लिए जरूरी है कि ज्यादा शहरों में स्टोर खोलने की इजाजत मिले। इसलिए कंपनियां शहरों की आबादी की सीमा को दस लाख के बजाय पांच लाख करने पर जोर दे रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय खरीद के नियमों को भी सिंगल ब्रांड रिटेल के मुताबिक आसान बनवाना चाहती हैं। अभी मल्टी ब्रांड रिटेल में उतरने वाली कंपनियों के लिए अपनी कुल खरीद का 30 फीसद घरेलू लघु इकाइयों से करने की शर्त है। सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है। माना जा रहा है कि डीआईपीपी कंपनियों के सुझावों के अनुरूप नीति में फेरबदल कर इस मुद्दे को फिर से कैबिनेट के सामने ले जाने पर विचार कर रहा है। ❑

पोस्को के लिये जमीन अधिग्रहण फिर शुरू

प्रस्तावित पोस्को परियोजना के लिये उड़ीसा सरकार ने गांव वालों के कड़े विरोध के बीच जमीन अधिग्रहण का काम फिर शुरू किया है। सरकार जुलाई तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा करना चाहती है और इसी के तहत ये कदम उठाये जा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार जबरिया उन्हें खेतों से बेदखल कर रही है और उनकी पान की खेती को बर्बाद कर रही है। जगतसिंह पुर जिले के कलेक्टर एस के मल्लिक ने संवाददाताओं से कहा कि हमें 52,000 करोड़ रुपये की परियोजना के लिये गोबिंदपुर गांव में 700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। जमीन अधिग्रहण का यह अंतिम चरण है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम पोस्को परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण कर रहा है। ❑

टाटा-बिड़ला-अम्बानी - खोलेंगे बैंक

u, बैंक लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक को 26 आवेदन मिले है। इन आवेदन जमा करने वालों में आदित्य बिड़ला समूह, टाटा कैपिटल, रेलिगेयर, रिलायंस कैपिटल सहित करीब तीन दर्जन कंपनियां नए बैंक लाइसेंस हासिल करने की दौड़ में हैं। जिन कंपनियों के निदेशक मंडलों ने बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन करने की मंजूरी दी है उनमें देश के सबसे पुराने वित्तीय संस्थान आईएफसीआई, आईडीएफसी, इंडिया इन्फोलाइन, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और डाक विभाग शामिल हैं। जहां केन्द्र सरकार को सरकारी ग्रामीण बैंकों को दुरुरूत करना चाहिए था वही दूसरी तरफ वह नए बैंक लाइसेंस के नाम पर प्राइवेट बैंकों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। ❑

सुस्त अर्थव्यवस्था की मार कार उद्योग पर

vFkZ;oLFkk में सुस्ती और ऊंची ब्याज दरों के बीच उपभोक्ता नए वाहनों की खरीदारी से दूर होते जा रहे हैं। इससे देश में वाहनों की लगातार घटकी बिक्री कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। बीते जून माह में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और इत्यादि दिग्गज कंपनियों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण अब कई कार कंपनियों ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों की छंटनी का खतरा भी मंडरा रहा है। वर्तमान समय में देश में करीब आठ लाख लोगों को वाहन उद्योग में रोजगार मिला हुआ है। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, सीईओ व प्रबंधन निदेशक अरविंद कपूर ने कहा कि कल–पुर्जा उद्योग में फिलहाल कोई नया निवेश नहीं हो रहा है, इसलिए नई नियुक्तियां नहीं हो रही है। हां अगर छह महीने तक स्थिति ऐसी ही बनी रही तो निश्चित तौर पर कुछ करना पड़ेगा। ❑

कहीं आपका दूध जहर तो नहीं

dgh आप जहर मिला दूध तो नहीं पी रहे हैं क्योंकि दूध की पौष्टिकता पर एक बार फिर सवाल उठा है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में मिलावटी दूध की बिक्री पर गंभीर चिंता जताई है। उत्तराखण्ड के स्वामी अच्युतानंद तीर्थ के नेतृत्व में नागरिकों के एक समूह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, रिफाइंड तेल, कॉस्टिक सोडा और सफेद पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकारों की ओर से कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा पूरे देश में हो रहा है। सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। पीठ ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली की सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपना जवाब दाखिल कर बताएं कि वे मिलावटी दूध पर रोक लगाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र ने कहा है कि इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से इस बाबत 31 जुलाई तक जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही प्रदेश सरकारों से ऐसे दूध की बिक्री पर रोक लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ❑

सोना नहीं रियल एस्टेट युवाओं की पहली पसंद

सोना और शेयर बाजार में हो रहे भारी उतार–चढ़ाव से घबराए देश के 85 प्रतिशत शहरी युवा वर्ग ने ऊंचे रिटर्न के लिए रियल एस्टेट में निवेश को अन्य क्षेत्रों के मुकाबले तरजीह दी है। यह खुलासा एसोचैम के सर्वे में हुआ है। सर्वे के अनुसार अब सोना, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश को जोखिमपूर्ण मानते हुए शहरी युवाओं ने रियल एस्टेट में निवेश करने को प्राथमिकता दी है। सर्वे में शामिल करीब 1500 लोगों ने माना कि सोना और शेयर की तुलना में आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति में निवेश अधिक सुरक्षित और मुनाफे वाला है। ❑

फ्री रोमिंग नहीं देना होगा कुछ शुल्क

vxj आप सस्ती रोमिंग मुफ्त होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो भूल जाए। काफी दिनों से फ्री रोमिंग की चर्चा हो रही थी लेकिन मोबाइल कंपनियां इसके लिए कतई तैयार नहीं थी हां अब कुछ शुल्क देकर आप सस्ती कॉल पा सकते हैं। एयरटेल और आइडिया ने तय शुल्क के साथ यह नई स्कीम पेश कर दी है। एयरटेल ने प्री–पेड उपभोक्ताओं के लिए पांच रुपए प्रति दिन के तय शुल्क के साथ असिमित कॉल करने की सुविधा पेशकश की है। वही आइडिया ने रोमिंग के लिए विभिन्न राज्यों के हिसाब से 230 रुपए और 240 रुपए के वाउचर के साथ स्कीम पेश की है। इसके तहत उपभोक्ता लोकल, एसटीडी और आईएसडी कॉल उसी दर पर कर सकेंगे। ❑

17 रुपए में कर रहे गुजारा

n'k के ग्रामीण इलाकों में सबसे गरीब लोग औसत महज 17 रुपए और शहरों में 23 रुपए प्रतिदिन में जीवन यापन करने को मजबूर है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। वर्ष 2011–12 (जुलाई–जून) के आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में निचले स्तर पर 5 प्रतिशत आबादी का प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 521. 44 पैसे रहा है, जबकि शहरी इलाकों में यह 700.50 रुपए। वही दूसरी ओर आबादी के शीर्ष 5 प्रतिशत का प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ग्रामीण इलाकों में 4,481 रुपए जबकि शहरी इलाको में 10,282 रुपए रहा। यह सर्वेक्षण 7,496 गांवों और शहरों में 5,263 इलाकों के नमूनों पर आधारित है। ❑

स्विस बैंक में जमा काला धन होने लगा कम

fiNy कुछ महीनों में भारतीयों के स्विस बैंक में जमा काले धन में एक–तिहाई की कमी आई है। इस खबर ने यह डर भी पैदा किया है कि क्या भारतीयों का काला धन विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर वापस भारत तो नहीं आ रहा? यह उस समय हो रहा है, जब रुपये का तेजी से अवमूल्यन हुआ है और डॉलर आसमान छू रहा है। इस समय विदेशों में जमा डॉलर को भारत लाने का अर्थ है, ज्यादा भारतीय मुद्रा हासिल करना। यह भी डर है कि कहीं यह पैसा किसी नए टैक्स हैवन में तो नहीं जा रहा। इसके साथ ही यूरोप एवं अन्य देशों द्वारा बैंकिंग संबंधी गोपनीयता कानून को ढीला करने के बाद वहां धन जमा करने वालों को अपनी सचाई उजागर होने का डर सताने लग गया है। लग्जेमबर्ग और ऑस्ट्रिया ने अपने बैंक संबंधी गोपनीयता कानूनों में ढिलाई देनी शुरू कर दी है। अब सारा ध्यान स्विट्जरलैंड की ओर केंद्रित हो गया है। करीब चार वर्ष पूर्व, स्वीट्जरलैंड ने अमेरिकी अधिकारियों के भारी दबाव के कारण अमेरिकी नागरिकों के बैंक खातों संबंधी सूचनाएं दी थीं। जैसे–जैसे टैक्स चोरों के प्रति लोगों के संयम का बांध टूटता जा रहा है, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की मार से बचने के लिए यूरोपीय संघ के देशों का दबाव स्विट्जरलैंड को अपने बैंकिंग कानून में बदलाव करने को मजबूर कर रहा है। वैसे केन्द्र सरकार के ढीले रवैया की वजह से स्विस बैंक ने अपने यहां जमा भारतीयों खातों का ब्यौरा और कोई भी सहयोग सरकार को नहीं दिया। ❑

अमरीका द्वारा कई देशों के दूतावासों की जासूसी

xr दिनों ब्रिटिश अखबार 'द गार्जियन' ने सीआईए के पूर्व तकनीकी सलाहकार एडवर्ड स्नोडेन से मिले खुफिया दस्तावेजों के हवालेसे मिले यह बात कही। अखबार के मुताबिक अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनएसए) केवल इंटनेट आंकड़ों की ही निगरानी नहीं करती बल्कि उसकी नजर वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास की गतिविधियों पर भी रहती है। एनएसए भारतीय दूतावासों सहित 38 देशों के दूतावासों की जासूसी करती है। इसके लिए व्यापक तरकीबों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक संचार की जासूसी से लेकर एंटीना के साथ ट्रांसमिशन संबंधी केबल में सेंध लगाना शामिल है। इससे पहले जर्मन समाचार पत्र डेर स्पेगल ने स्नोडेन द्वारा लीक दस्तावेजों के हवाले से एक और खुलासा किया था। इसमें एनएसए द्वारा वाशिंगटन और न्यूयार्क स्थित यूरोपीय संघ के दूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों की जासूसी की थी। एजेंसी ने ब्रसेल्स में उसके कार्यालय के कंप्यूटर में भी सेंधमारी की थी। ❑

भविष्य निधि पर 8.5 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्ष 2013–14 में भी अपने पांच करोड़ अंशधारकों को भविष्य निधि जमा (पीएफ) पर 8.5 फीसदी की ब्याज जारी रखने की संभावना है। 2012–13 में भी भविष्य निधि पर 8.5 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है। हालांकि, इससे पहले वित्तवर्ष 2011–12 में भविष्य निधि पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज दिया गया। ❑

इंटरनेट द्वारा हुए 2,152 फिशिंग हमले

fQf'kx एक प्रकार का ठगी का तरीका है जिसमें एक तरह से वैध कंपनियों के जरिये ई–मेल भेजना दिखाया जाता है, जिससे लोगों को अपनी निजी जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सके। दुनिया भर में इंटरनेट पर फिशिंग हमलों में भारत का हिस्सा करीब 8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 13.7 करोड़ है। अप्रैल में भारत में 2,152 फिशिंग हमले हुए। अप्रैल में दुनिया भर में जितने फिशिंग हमले हुए उनमें से 8 फीसदी भारत में इंटरनेट नेटवर्क पर किए गए। आईटी स्टोरेज साल्यूशंस फर्म ईएमसी के मुताबिक, फिशिंग हमलों के मामले में भारत का स्थान अमेरिका, ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका के बाद चौथे स्थान पर आता है। ❑

300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय होंगे

राष्ट्रीय दवा मूल्य–निर्धारण प्राधिकार (एनपीपीए) के अध्यक्ष सी.पी. सिंह ने कहा कि हम जल्द ही थोक दवाओं के आधार पर करीब 300 दवाओं के अधिकतम मूल्य तय करेंगे। इसमें वे 237 दवाएं भी शामिल होंगी जिनके अधिकतम मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं। इस पहल से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। दवा उद्योग के जानकार लोगों के मुताबिक नई दवा नीति लागू करने से कई कैंसर रोधी और संक्रमण रोधी दवाओं की कीमत 50–80 प्रतिशत घट जाएगी। एनपीपीए की यह पहल दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद की गई है जो 15 मई से लागू है। उक्त आदेश 1995 में जारी आदेश की जगह लेगा। ❑

गरीबी घटाने के लक्ष्य को 2015 तक हासिल करेगा भारत

देश में गरीबी की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत गरीबी में कमी के एमडीजी लक्ष्य को 2015 तक हासिल कर लेगा। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की जारी एमडीजी रिपोर्ट में कहा गया है, हालांकि, भारत में गरीबी व्यापक स्तर पर फैली है और इस दिशा में प्रगति उल्लेखनीय है। भारत में गरीबी की दर 1994 में 49 प्रतिशत थी, जो 2005 में घटकर 42 प्रतिशत पर और 2010 में 33 प्रतिशत पर आ गई। यदि यही रफ्तार जारी रहती है, तो भारत 2015 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया में अत्यंत गरीबी की दर तय समयसीमा से पांच साल पहले ही आधे पर आ गई है। हालांकि, इस मामले में भारत अपवाद रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोआर्डिनेटर लीस ग्रैंड ने कहा कि आठ लक्ष्यों से जुड़े 21 वैश्विक लक्ष्यों में से छह बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य पहले ही हासिल हो गए हैं। इनमें से सबसे उल्लेखनीय लक्ष्य वैश्विक स्तर पर बेहद गरीब आबादी में 50 प्रतिशत की कमी है। ❑

आधी आबादी आपदा क्षेत्र में

उत्तराखंड के प्राकृतिक विनाश ने दुनिया के सभी लोगों को हिलाकर रख दिया है। विश्व बैंक का कहना है कि आधी से ज्यादा दुनिया आपदा वाले इलाकों में बसी है। ऐसे में जान–माल की हानि तय है। पर्यावरण विरोधी गतिविधियों को रोककर, बेहत प्रणाली से इसे कम किया जा सकता है। आज 20 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी का प्राकृतिक आपदा के लिहाज से संवेदनशील है। करीब 3.5 अरब से ज्यादा लोग इन हिस्सों में रह रहे है। 160 देशों की एक चौथाई आबादी ऐसे क्षेत्रों में बसी है, जहां आपदा से मौत का खतरा काफी अधिक है। 90 फीसदी आपदा से जुडी मौते विकासशील और गरीब देशों में होती है। भारत, चीन, मैक्सिको और ब्राजील की आध ी जीडीपी आपदा के लिहाल से संवेदनशील इलाकों में आती है। करीब 21 फीसदी मानवीय मदद का इस्तेमाल आपदा से लडने और उससे निपटने के उपाय तलाशने में करना पड़ता है। विशेषज्ञों की मानें तो बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदायें इन देशों के विकास पर करती है सबसे ज्यादा चोट। ❑

प्याज, टमाटर के बढ़ते दाम से उपभोक्ता परेशान

tu–जुलाई माह देश के आम नागरिक कई संकटों से गुजर रहे हैं। एक ओर उत्तराखंड में हुई दैवी आपदा, दूसरी तरफ हिमाचल में भारी वर्षा और यमुना नदी में आई बाढ़ से सब्जियों के दाम काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। टमाटर की फसल को हुए भारी नुकसान की वजह से इसके दाम खुले बाजार में 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। प्याज भी पिछले एक पखवाडे के दौरान सुर्ख होकर 50 प्रतिशत तक महंगी हो गई है। साथ ही कालाबाजारी का कारोबार भी चरम सीमा पर हो रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार चुपचाप यह तमाशा देख रही है। जिसका परिणाम आम उपभोक्ता भोग रहा है। ❑

विदेशी कर्ज हुआ 390 अरब डॉलर

Hkkjr पर विदेशी कर्ज पिछले वित्त वर्ष के दौरान 13 फीसद बढ़कर 390 अरब डॉलर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में बताया कि छोटी अवधि के कर्ज और विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) में इजाफे के चलते विदेशी कर्ज में इजाफा हुआ है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2012 में कर्ज का 85.2 फीसद था। यह मार्च, 2013 में घटकर 74.9 फीसद रह गया। ट्रेड क्रेडिट की वजह से विदेशी कर्ज बढ़ता चला गया। इस दौरान छोटी अवधि के क्रेडिट बढ़े। वहीं ईसीबी और रुपये आधारित एनआरआइ जमा में भी इजाफा हुआ। इन सभी कारणों ने विदेशी कर्ज को बढ़ने का मौका दे दिया। ❑

कम हुई घरेलू बचत

जीडीपी के मुकाबले कुल घरेलू बचत कम होकर 30.8 फीसद रही है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, वित्त वर्ष 2008 में यह 36.8 फीसद तक पहुंच गई थी। घरेलू बचत में कमी के लिए आरबीआइ ने लोगों द्वारा वित्तीय सेवाओं में निवेश से दूरी बनाने को जिम्मेदार ठहराया है। यह जीडीपी का आठ फीसद ही रहा है।❑

10 हजार नौकरियां देगा एसबीआई

n'k का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई शीघ्र ही 10 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती करेगा। बैंक ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नई भर्तियों की यह योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार बैंक के करीब 7,500 कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और 1500 अधिकारी और पीओ सहित 10 लोगों को रोजगार देगा। ❑

खाद्य सुरक्षा योजना से और बढ़ेगी महंगाई

जैसे–जैसे चुनाव पास आ रहे है केंद्र सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को लागू कर दिया है। इससे देश के राजस्व को कितना घटा होगा उसकी चिंता सरकार किसी को नहीं है। जहां सर्वोच्च न्यालय ने कई बार अपने फैसले में कहा है कि जो अनाज खुले आसमान के नीचे सड़ रहे है उन्हें मुफ्त में गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। परंतु उस ओर ध्यान न देकर अपनी महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना से खाने–पीने की चीजों की महंगाई को और भड़काएगी।

विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों का मानना है कि कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए खाद्य सुरक्षा बिल लाई है। इसका गरीबों से कोई संबंध नहीं। जब भुखमरी से मौतें हो रही थीं, तब गोदामों में भरा गेहूं गरीबों में वितरित क्यों नहीं किया। गेहूं, चावल चूहे खाते रहे और कुछ सड़ गया। कई दलों ने कहा कि अगर खाद्य सुरक्षा बिल में अगर किसानों का हित नहीं दिखा तो वह संसद सत्र में बिल का समर्थन नहीं करेंगे।

वही फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसीडेंट पी शिवकुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी। इस रकम की जरूरत करदाताओं से ही पूरी की जाएगी। सरकारी खर्च में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद विकास दर में सुधार और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगारों का निर्माण इस समय सबसे जरूरी है। बेहतर रोजगार की कमी और मुफ्त राशन वितरण जैसी योजनाओं के कारण गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग बेहद कम आय में गुजारा करने के आदी हो जाते हैं। इस स्थिति को छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के कारण लोगों के आलसी होने से यह स्थिति पैदा होती है। भारत जैसे विकासशील देश में कौशल निर्माण करना बेहद जरूरी है। बेहतर भंडारण और वितरण सुविधाएं विकसित करने के लिए सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है। सरकारी खरीद में भारी बढ़ोतरी के कारण राजकोषीय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके चलते करदाताओं पर बोझ भी बढ़ रहा है। ❑

खाद्य सुरक्षा योजना से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा

यूपीए–2 सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना देश में लागू करने के बाद। देश के बड़े–बड़े अर्थशास्त्रीयों और उद्योग जगत और बैंकों ने भी इस योजना पर सवाल उठा दिए हैं। अब डीबीएस बैंक का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के निर्णय से चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत के लक्ष्य से आधा प्रतिशत आगे बढ़ सकता है। इससे मामला और जटिल बन सकता है। सिंगापुर स्थित इस ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस साल राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य से कम से कम आधा प्रतिशत ऊपर जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्सिडी बिल बढ़कर जीडीपी के 2.3 प्रतिशत तक पहुंच सकता है जो 1.9 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर है। सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी की मुख्य वजह व्यापक स्तर पर खाद्य सब्सिडी होगी। राजकोषीय मोर्चे पर रुपए में गिरावट और बाद में कच्चे तेल में तेजी, आग में घी डालने जैसा काम करेगी। खाद्य सुरक्षा विधेयक के जरिए देश की दो–तिहाई आबादी को 1 से 3 रुपए प्रति किलो की दर पर हर महीने 5 किलो खाद्यान्न का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। ❑

मुफ्त की घोषणाओं पर लगे लगाम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि घोषणापत्रों में मुफ्त लैपटॉप, टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, बिजली का पंखा और सोने की थाली देने जैसी लोक लुभावन घोषणाएं भले ही जनप्रतिनिधित्व कानून में भ्रष्टाचार की परिभाषा में न आती हो लेकिन इनसे लोग प्रभावित होते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया दूषित करती हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह घोषणापत्रों में मुफ्त उपहार की लोक लुभावन घोषणाएं रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करे ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। इतना ही नहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह इसे महत्वपूर्ण मानते हुए जल्दी से जल्दी अंजाम दे। कोर्ट ने इस बारे में राजनैतिक दलों को नियमित करने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत पर भी बल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर राजनीतिक दलों में बहस चल रही है। वही दूसरी ओर अगर कोई राज्य सरकार अगर लैपटॉप, साइकिल या कोई अन्य लोकलुभावन योजना चलाती है तो योजना आयोग को इससे ऐतरात नहीं है। योजना आयोग के अनुसार लोक लुभावन वादों पर रोक लगाना काफी मुश्किल है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगे बढ़कर घोषणा पत्रों के विनियमन पर दिशा–निर्देश बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के कार्यक्रमों जैसे सड़क, बांध, स्कूल, खेल के मैदान आदि चीजों के वादे घोषणापत्रों में कर सकते हैं। वहीं वादे सामान्य किस्म के होने चाहिए लेकिन इनकी पूर्ति भी संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होनी चाहिए। ❑

बदहाली अर्थव्यवस्था के गुनहगार

ljdkj d dk;dky e u doy #i;k fxj jgk g] cfYd n'k dh lk[k Hkh [kkd gk jgh gA ljdkj l turk dk fo'okl mBk gA okLrfodrk rk ;g g fd ç/kkue=h u ljdkj rk Hky gh pykb] fdr vke vkneh dh xk<h dekbl tk jk tdk"k ,d= gkrk g ml [kp dju dk fun'k lkfu;k xk/kh uhr ^jk"Vh; lykgdkj ifj"kn* nrh gA bl ifj"kn dk lkjk /;ku dkxl dk pukoh ykHk fnyku d fy, ykd&yHkkou uhfr;k cuku ij dfær g] ftld dkj.k u doy jktdk"k ij Hkkjh ck> c<k g] cfYd iVjh l mrj pdh vFk0;oLFkk ml <ku e ukdke lkfcr gk jgh gA

■ बलवीर पुंज

अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपये की ताकत में लगातार आ रही गिरावट क्या रेखांकित करती है? यदि शरीर का तापमान व्यक्ति के स्वास्थ्य को इंगित करता है तो निरूसंदेह देश की मुद्रा वहां की अर्थव्यवस्था का हाल बयान करती है। भाजपानीत राजग के समय में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 40 रुपये प्रति डॉलर थी। आज उसकी कीमत साठ रुपये के करीब आ पहुंची है। इसका अर्थ हुआ कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के कार्यकाल में रुपये की कीमत में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। रुपये की क्रयशक्ति घटने का सीधा अर्थ है कि इससे अंततोगत्वा आम आदमी की जरूरत की हर वस्तु महंगी मिलेगी। आर्थिक आंकड़े संप्रग–2 की नाकामी उजागर कर रहे हैं, किंतु सरकार अपने नौ साल की कथित उपलब्धियों पर जश्न मना रही है।

हाल ही में संप्रग सरकार के पिछले चार साल का रिकार्ड जारी करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दावा किया कि उन्हें विरासत में आधा भरा गिलास मिला था, जिसे उन्होंने भरने की पूरी कोशिश की और अभी पूरा भरने में थोड़ी कसर बाकी रह गई है। प्रधानमंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है? भाजपानीत राजग सरकार से इस सरकार को जैसी अर्थव्यवस्था हाथ लगी थी उसका विश्लेषण करने पर सरकार के लिए अपनी कथित उपलब्धियों का जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। संसद में संप्रग सरकार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन वित्तामंत्री पी. चिदंबरम ने स्वीकार किया था कि उन्हें विरासत में एक मजबूत अर्थव्यवस्था मिली है। मुद्रास्फीति की दर अंकुश में है और रोजगार के यथेष्ट अवसर उपलब्ध हैं। 2004 में सत्ता परिवर्तन के ठीक बाद आयोजित 20वें आर्थिक शिखर सम्मेलन में पी. चिदंबरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया था। वित्तामंत्री ने तब कहा था, 'पहली बार भारत को विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में पहचाना जा रहा है।' तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था पर ग्रहण कैसे लगा?

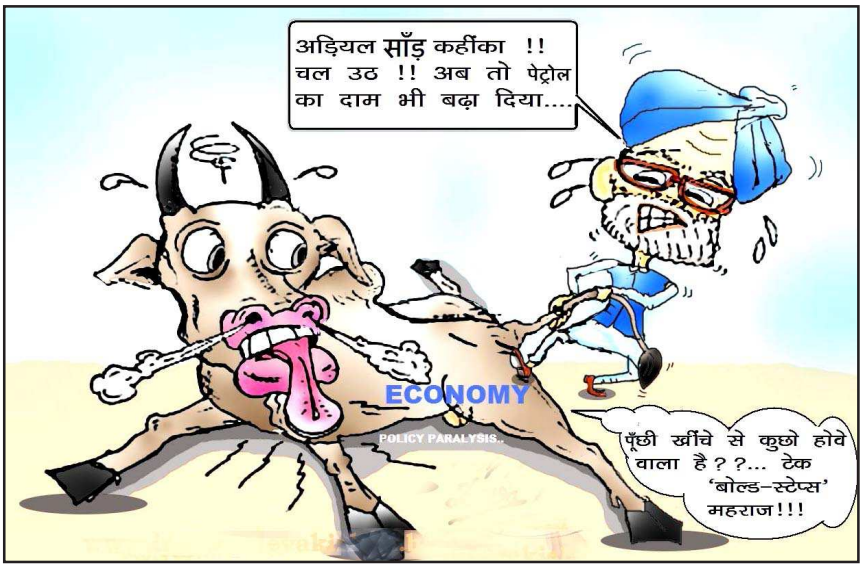

वर्ड इकोनॉमिक फोरम की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006–07 में प्रतिस्पर्द्धा की दृष्टि से भारत का दुनियाभर में 42वां स्थान था, जो 2012–13 में गिरकर 56 पर आ गया। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भारत 62वें स्थान से गिरकर 84वें और बिजली के क्षेत्र में 110वें स्थान से गिरकर 144वें स्थान पर आ गया है। यह बदहाली क्यों आई?

राजग को 1997 में सत्ता में आने पर 4.9 प्रतिशत विकास दर वाली अर्थव्यवस्था

मिली थी। राजग के कार्यकाल के आखिरी तिमाही में आर्थिक विकास की दर 8.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी। नौ सालों के बाद अर्थव्यवस्था पुनरू 1997 की स्थिति में पहुंच गई है। औद्योगिक विकास दर 3.1 प्रतिशत है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर 1.9 प्रतिशत है। जीडीपी में कृषि का योगदान 1998 और 1999 में क्रमशरू 26 और 25 फीसद था, जो संप्रग की पहली पारी की समाप्ति पर गिरकर 18 प्रतिशत और 2011 में 17 प्रतिशत रह गया।

राजग के कार्यकाल की समाप्ति पर महंगाई की दर 3.8 प्रतिशत थी, जो 2010 में करीब तीन गुना की रफ्तार से बढ़कर 12 प्रतिशत पर दर्ज हुई। पिछले नौ सालों में भारत के वाच् कर्ज में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। 2001 में देश पर वाह्य कर्ज 118 अरब डॉलर था। दिसंबर, 2012 में यह बढ़कर 376.3 अरब डॉलर हो गया है, जबकि मार्च, 2012 में यह 345.5 अरब डॉलर था। भारतीय मुद्रा में कहें तो मार्च, 2012 में वाच् कर्ज 17,65,978 करोध रुपये था, जो दिसंबर, 2012 में बढ़कर 20,60,904 करोध रुपये हो गया अर्थात केवल नौ महीनों में वाह्य कर्ज में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आज भारत के हर नागरिक पर 33,000 रुपये का कर्ज है। इसका जिम्मेदार कौन है?

संप्रग सरकार में सत्ता के दो केंद्र होने के कारण ही देश में चारो ओर बदहाली का आलम है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा अर्थशास्त्री विवश है। उसके पास पद है, किंतु शक्ति नहीं है और जिसके पास शक्ति है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार लोक–लुभावन योजनाओं का ढिंढोरा पीट चुनावी लाभ लेने के लिए बेताब है।

^fcgkj] egkjk"V™ vkj mÙkj çns'k es Hkkjr ds xjhcks dh 46 çfr'kr vkcknh clrh g] fdrq euj sxk ;kstuk ds fy, fuxr dy jkf'k dk 20 çfr'kr fgLlk gh bu jkT;ks ds fy, Loh—r fd;k x;kA* [kk| lqj{kk ;kstuk es djhc 1]24]000 djkM+ #i;s gj lky [kpZ gksxA bldk ckš dkSu <ks,xk\ ns'k ds xksnkeks es gtkjks Vu [kk|ké lM+ tkrk g] vnkyr us mUgs xjhcks es forfjr djus dk l|>ko Hkh fn;k FkkA bl fn'kk es dksbZ rdZlxr mik; D;ks ugh lkpk x;k

मनरेगा के बाद अब सरकार खाद्य सुरक्षा बिल के पीछे लगी हुई है। मनरेगा योजना पर पिछले सात सालों में 19 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए, किंतु मानव श्रम दिवस के सृजन में 26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। कैग की रिपोर्ट मनरेगा की कलई खोलती है। कैग ने कहा है, 'बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भारत के गरीबों की 46 प्रतिशत आबादी बसती है, किंतु मनरेगा योजना के लिए निर्गत कुल राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा ही इन राज्यों के लिए स्वीकृत किया गया।' खाद्य सुरक्षा योजना में करीब 1,24,000 करोड़ रुपये हर साल खर्च होंगे। इसका बोझ कौन ढोएगा? देश के गोदामों में हजारों टन खाद्यान्न सड़ जाता है, अदालत ने उन्हें गरीबों में वितरित करने का सुझाव भी दिया था। इस दिशा में कोई तर्कसंगत उपाय क्यों नहीं सोचा गया?

वस्तुतः इस सरकार की एकमात्र उपलब्धि भ्रष्टाचार के नित नए आयाम गढ़ना है। कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर कोयला घोटाले तक देश को करीब 6.25 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कानून को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए। सरकार का तर्क था कि देश को ऊर्जा संकट से उबारने के लिए यह बहुत जरूरी था। अदालत की फटकार के बाद इसकी सीबीआइ जांच हुई। कई आवंटन निरस्त हुए। जांच की आंच सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी है। इस मामले में कानूनमंत्री का पहले ही इस्तीफा हो चुका है। अब कोयला घोटाले में कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोयला आवंटन लेने और तत्कालीन कोयला राज्यमंत्री दासारी नारायण राव को 2.25 करोड़ रुपये देने के आरोप में सीबीआइ ने केस दर्ज किया है। यहां यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोयला आवंटन के सारे खेल के दौरान सभी कोयला राज्यमंत्री जहां कांग्रेसी थे, वहीं कोयला मंत्रालय का प्रभार स्वयं प्रधानमंत्री संभाल रहे थे।

इस सरकार के कार्यकाल में न केवल रुपया गिर रहा है, बल्कि देश की साख भी खाक हो रही है। सरकार से जनता का विश्वास उठा है। वास्तविकता तो यह है कि प्रधानमंत्री ने सरकार तो भले ही चलाई, किंतु आम आदमी की गाढ़ी कमाई से जो राजकोष एकत्र होता है उसे खर्च करने का निर्देश सोनिया गांधी नीत 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद' देती है। इस परिषद का सारा ध्यान कांग्रेस को चुनावी लाभ दिलाने के लिए लोक–लुभावन नीतियां बनाने पर केंद्रित हैं, जिसके कारण न केवल राजकोष पर भारी बोझ बढ़ा है, बल्कि पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था उसे ढोने में नाकाम साबित हो रही है। ❑

विचार

सिर्फ बातों से नहीं उठेगा रुपया

cfu;knh rkj ij vFk0;oLFkk ,d detkj fLFkfr l xtj jgh gA fon'kh fuo'kd rk Hkkjrh; vFk0;oLFkk dk vfo'okl dh fuxkg l n[k gh jg g] n'kh fuo'kd Hkh Hkkjrh; vFk0;oLFkk d çfr vk'oLr ugh gA fuo'k flQ oreku fLFkfr dk n[kdj ugh vkrkA fuo'k Hkfo"; dh mEehnk ij Hkh vk/kkfjr gkrk g vlyh jkgr rk fon'kh vk|kfxd fuo'k e gh fufgr gA ij ; ,l ugh vkrk] tl vFk0;oLFkk py jgh gA

■ आलोक पुराणिक

रुपया डूब रहा है, यह खबर पुरानी हो गई है। रुपया बहुत गहराई में जाकर डूब रहा है, यह खबर भी नई नहीं है। रुपया डूबने के बाद उबरने से इनकार कर रहा है, यह खबर कुछ नई हो सकती है। एक डॉलर के बदले अब साठ रुपये से कुछ ज्यादा मिल रहा है। कुछ समय पहले एक डॉलर के बदले पचपन रुपये मिल रहे थे। तब भी बातें हो रही थीं कि रुपया सुधरेगा और मजबूत होगा।

पर बातों से कुछ नहीं होता। बातों से तो सिर्फ बातें तक नहीं हो सकती हैं, बातें करने के लिए भी जीवित रहने की जरूरत होती है। जीवित रहने के लिए खाने–पीने की जरूरत होती है। उसके लिए कुछ श्रम करने की जरूरत होती है। श्रम के बगैर वही जीवित रह सकता है, जिसके पास पुरानी पीढ़ियों का संचित धन हो। भारतीय अर्थव्यवस्था का हाल अभी इस तरह की नहीं है जिसमें पुरानी पीढ़ियों का संचित धन उपलब्ध हो। रोजनदारी दिहाड़ी की अर्थव्यवस्था जैसा कुछ सीन बन रहा है। थोड़ी भी कमाई रुपए के, तो आफत दिखती है। रुपया डूब रहा है, उसके पीछे यही आफत है।

साठ के पार गए रुपये को बिंब की भाषा में रिटायर हुआ माना जा सकता है। पर सचाई यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जो उम्मीदें दुनिया भर के निवेशक कर रहे थे, वे अब रिटायर हो रही हैं। रुपये की कमजोरी की कहानी उम्मीदों के रिटायर होने से जुड़ी है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता है!

किसी भी आइटम की तरह रुपये की मांग कम होती है, तो रुपया कमजोर होता है। डॉलर मजबूत क्यों होता है, किसी भी आइटम की तरह डॉलर की मांग ज्यादा होती है, तो डॉलर मजबूत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब विदेशी निवेश डॉलर की शक्ल में आता है, तो भारत का विदेशी मुद्रा कोष मजबूत होता है। डॉलर यहां आते हैं और रुपयों में तब्दील होकर यहां की अर्थव्यवस्था में लगते हैं। यह दौर रुपये की मजबूती का दौर होता है। डॉलर जब यहां से वापस लौटते हैं, तो विदेशी निवेशक यहां बिकवाली करते हैं। फिर बिकवाली से हासिल रुपयों को डॉलर में बदलकर अपने देश ले जाते हैं।

डॉलर ले जाते हैं, तो डालर की मांग बढ़ती है। डालर की मांग बढ़ेगी, तो

lêckth d fy, vku oky Mkyj {kf.kd jkgr ykr g] ij vlyh jkgr rk fon'kh vk|kfxd fuo'k e gh fufgr gA ij ;g ,l ugh vkrk] tl vFk0;oLFkk py jgh gA foÙk e=h ih fpnacje fo'o d reke n'kk e tkdj xgkj yxk vk, fd Hkkjr e fon'kh fuo'k ykvk] ij mudh xgkj tl bl dku ludj ml dku l fudky nh xb gA

तार्किक तौर पर डॉलर की मजबूती बढ़ना तय होता है। डॉलर की मांग बढ़ना, रुपये का कमजोर होना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं है कि रिजर्व बैंक भारत में डॉलर को खरीद रहा है या बेच रहा है। रिजर्व बैंक के डॉलर खरीदने या बेचने का बाजार पर थोड़े वक्त तक असर हो सकता है, पर बुनियादी तौर पर तो अर्थव्यवस्था के तमाम कारक रुपये की कमजोरी या मजबूती तय करेंगे। बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था एक कमजोर स्थिति से गुजर रही है। विदेशी निवेशक तो भारतीय अर्थव्यवस्था को अविश्वास की निगाह से देख ही रहे हैं, देशी निवेशक भी भारतीय अर्थव्यवस्था को अविश्वास की निगाह से ही देख रहे हैं। निवेश सिर्फ वर्तमान स्थिति को देखकर नहीं आता। निवेश भविष्य की उम्मीदों पर भी आधारित होता है।

रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा को जब उदार बनाया गया था, तब उम्मीद की गई थी कि विदेशी निवेशक इस क्षेत्र में धुआंधार निवेश लेकर आएंगे। पर अब सामने यह है कि विदेशी निवेशक रिटेल में पैसा लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उदार नीतियां भर बनाने से स्थितियां नहीं सुधरतीं। जब तक विदेशी निवेशक आश्वस्त नहीं होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नीतिगत सातत्य है, कुछ ठोस करने की नीतिगत इच्छाशक्ति है, तब तक विदेशी निवेशक अपना पैसा न तो औद्योगिक निवेश के जरिए, न शेयर बाजार में निवेश के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था में लाएंगे, यही हो रहा है।

लाना तो दूर, जो पैसा विदेशी निवेशकों ने लगाया है, उसे वापस ले जाने की सोचेंगे। बल्कि सोच रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में यही रुख अपनाया हुआ है। इस वजह से डॉलर बाहर जाते दिख रहे हैं।

2012–13 के अंत यानी मार्च, 2013 में विदेशी कर्ज 390 अरब डॉलर का था। मार्च, 2012 के अंत के मुकाबले इसमें करीब तेरह प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस इजाफे की एक वजह यह है कि तमाम कंपनियों ने विदेश से काफी कर्ज लिया है। यानी विदेशी कर्ज में इजाफा हुआ है ऐसे वक्त, जबकि विदेशी निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने में रुचि कम की है। विदेशी मुद्रा कोष में रकम लाने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर जो तरीका सबसे अच्छा और दीर्घकालिक तौर पर बेहतर माना जाता है, वह यह है कि विदेशी निवेशक आएं और यहां के उद्योगों में निवेश करें या नए उद्योग लगाएं। ऐसा निवेश लंबे समय तक टिकता है और अर्थव्यवस्था का भला करता है। शेयर बाजार में लगे डॉलर कब फुर्र हो जाएंगे, कुछ पक्का नहीं रहता। इसलिए शेयर बाजारों में लगे डॉलर कई बार सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजी के लिए आते हैं, निवेश के लिए नहीं।

सट्टेबाजी के लिए आने वाले डॉलर क्षणिक राहत लाते हैं, पर असली राहत तो विदेशी औद्योगिक निवेश में ही निहित है। पर यह ऐसे नहीं आता, जैसे अर्थव्यवस्था चल रही है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम विश्व के तमाम देशों में जाकर गुहार लगा आए कि भारत में विदेशी निवेश लाओ, पर उनकी गुहार जैसे इस कान सुनकर उस कान से निकाल दी गई है। विदेशी निवेशक नीतिगत सातत्य चाहते हैं, वह फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। एक साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर चार कन्नौजिया और चौबीस चूल्हे की कहावत चरितार्थ होती है, तो एनडीए गठबंधन में तो अभी से साफ हो रहा है कि कन्नौजिया चाहे एक भी कायदे का न हो, पर चूल्हे एक सौ चौबीस अभी से दिख रहे हैं। राजनीतिक अनिश्चितता विकट दिख रही है।

तीसरा मोर्चा सिर उठाने की कोशिश में रहता है। अब तो पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों द्वारा फेडरल फ्रंट की बात की जा रही है। यानी चौथे मोर्चे के अंकुर भी फूट रहे हैं। ऐसे में भविष्य में किसी नीतिगत सुस्पष्टता के बजाए आपसी लेनदेन पर आधारित सरकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक अनिश्चितता विकट है, तो रिटेल में विदेशी निवेश नीति का क्या होगा, अभी यह साफ नहीं है।

टेलीकॉम, एविएशन समेत तमाम सेक्टरों में स्थिति बहुत साफ नहीं है। जितने स्पष्टीकरण हैं, उन पर ही कंफ्यूजन हैं। कुल मिलाकर ऐसे विकट कंफ्यूजन वाले राजनीतिक समय में स्पष्ट आर्थिक नीतियों की उम्मीद बेमानी ही है। पर हालात भविष्य में बेहतर होंगे ऐसी आश्वस्ति भी किसी विदेशी निवेशक को नहीं है। इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत सुधरती दिख रही है। दुनिया भर की कंपनियां वहां निवेश करके सुरक्षित रिटर्न कमाना पसंद करेंगी। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भारत बतौर निवेश–केंद्र उतना निवेश आकर्षित नहीं कर पा रहा है, जितना कुछ सालों पहले कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में रुपये का डूबना साफ दिख रहा है।

सिर्फ डूबना ही नहीं, डूबे रहना भी साफ दिख रहा है। डूबते रुपये को उबारने के लिए ठोस कदम चाहिए, पर वे हैं नहीं। सिर्फ बातें हैं, और सिर्फ बातों से बातें भी नहीं हो सकतीं। ❑

दृष्टिकोण

घट रही है विकास दर, बढ़ रही बेरोजगारी

fofHké jkstxkj lo{k.kksa esa ;g ckr Hkh mHkjdj lkeus vk jgh gS fd Åaph çksQs'kuy fMxzh j[kus okys djhc 20 Qhlnh fo|kfFkZ;ksa dks gh vPNk jkstxkj çkIr gks jgk gS] tcfd 47 Qhlnh xzstq,V jkstxkj ds yk;d gh ugha gSaA tks Nk= dai;wVj] vkbZVh] çca/ku tSlh fo'ks"kKrk ds lkFk J"Bre 'kS{kf.kd laLFkkuksa ls f'kf{kr&çf'kf{kr gksdj vk jgs gSa] mUgsa cM+h&cM+h daifu;ka eksVs osru ij jkstxkj ns rks jgh gSa] ij nwljh vksj] fMxzh gkFk esa fy, gq, yk[kksa ;qok jkstxkj dh ryk'k esa HkVd jgs gSaA

■ जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा देश में बेरोजगारी के बारे में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि जून, 2010 से जून, 2012 के बीच बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। पिछले दो साल के दौरान देश में बेरोजगारी 10.2 फीसदी की दर से बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी, 2012 में देश में पूर्ण बेरोजगारों की संख्या 1.08 करोड़ थी, जबकि दो साल पहले यह आंकड़ा 98 लाख था। इस आंकड़े के अलावा कई सरकारी एवं गैरसरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़े भी बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी की बात कह रहे हैं।

योजना आयोग के मुताबिक, देश में 3.60 करोड़ पूर्ण बेरोजगार हैं। कुछ सर्वेक्षणों में पूर्ण बेरोजगारों की संख्या जहां पांच करोड़ के लगभग बताई जा रही है, वहीं अन्य प्रकार के अर्ध बेरोजगारों एवं मौसमी बेरोजगारों की संख्या इससे तीन गुना अधिक बताई जा रही है। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन, एसोचौम के अध्ययन के अनुसार, हाल के वर्षों में आर्थिक विकास दर में तो वृद्धि हुई है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार में गिरावट आई है। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में जो विदेशी निवेश आया है, वह रोजगार में तब्दील नहीं हो सका है। कृषि क्षेत्र में रोजगार कम हुए हैं। औद्योगिक विकास दर कम रही है। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर मंद गति से बढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश की कमी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे।

विभिन्न रोजगार सर्वेक्षणों में यह बात भी उभरकर सामने आ रही है कि ऊंची प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले करीब 20 फीसदी विद्यार्थियों को ही अच्छा रोजगार प्राप्त हो रहा है, जबकि 47 फीसदी ग्रेजुएट रोजगार के लायक ही नहीं हैं। जो छात्र कंप्यूटर, आईटी, प्रबंधन जैसी विशेषज्ञता के साथ श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षित–प्रशिक्षित होकर आ रहे हैं, उन्हें बड़ी–बड़ी कंपनियां मोटे वेतन पर रोजगार दे तो रही हैं, पर दूसरी ओर, डिग्री हाथ में लिए हुए लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। कई युवा बतौर पेशेवर पहचान इसलिए नहीं बना पा रहे, क्योंकि देश के अधिकांश शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है। अनेक इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों को प्रैक्टिकल कराए बिना ही ग्रेजुएट बना दिया जा रहा है। देश के अधिकांश कॉलेजों–विश्वविद्यालयों का ध्यान सिर्फ एमबीए और अन्य विषयों के छात्रों को प्लेसमेंट प्रक्रिया में बैठाने तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। छात्रों के समग्र विकास के लिए वे कुछ खास नहीं कर पा रहे।

vkfFkZd mnkjhdj.k ds ckn ns'k esa tks fons'kh fuos'k vk;k gS] og jkstxkj esa rCnhy ugha gks ldk gSA —f"k {ks= esa jkstxkj de gq, gSaA vkS|kfxd fodkl nj de jgh gSA eSU;wQSDpfjax lsDVj esa jkstxkj ds volj ean xfr ls c<+ jgs gSaA cqfu;knh <kaps ds {ks= esa fuos'k dh deh ls jkstxkj ds volj ugha c<+ ik jgsA

उद्यमपरक मानव संसाधन तैयार करने की ओर अब भी सरकारें, सक्षम प्राधिकरण व अन्य संबंधित संगठन ज्यादा संजीदा नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए न तो प्रशिक्षण व पढ़ाई के स्तर पर ठोस पहल की जा रही है, न बाजार के अनुरूप रोजगार के लिए माहौल विकसित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में प्रोफेशनल शिक्षा के जो गिने–चुने संस्थान हैं, वहां प्रवेश और ऊंची फीस की व्यवस्था दुष्कर कार्य है। ऐसे में पर्याप्त संख्या में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर, किंतु प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छा रोजगार पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

इस देश में 1,200 से अधिक पॉलीटेक्निक और 5,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। हजारों की संख्या में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं। पर स्थिति

¼'ks"k i"B 33 ij---½

देसी दूध व्यापार पर विदेशी कुचक्र

;jkfi;u ;fu;u e nèk cpu okyk d cM Qke gkr g ftUg Hkkjh lfClMh feyrh gA vr% Hkkjr d NkV i'kikydk dk mul çfrLièkk d fy, etcj djuk cgr vU;k;i.k gA nkuk dh fLFkfr;k cgr fHké gA ij ;fn eä 0;kikj le>krk gkrk g rk ;jkfi;u ;fu;u d nXèk mRiknk & tl nèk d ikmMj] cVj v,;y] iuhj vkfn ij fu;=.k vk;kr&'kYd ugh d cjkcj gk tk,xkA blls lLr ;jkfi;u vk;kr Hkkjr d cktkj ij Nk tk,x o Hkkjr d nèk mRikndk l mud viu n'k dk cktkj gh dkQh gn rd fNu tk,xkA

■ **भारत डोगरा**

देश के शहरी बाजार में आज दूध की प्रचुरता जरूर नजर आती है पर यदि दूध उत्पादन व डेयरी उद्योग के विभिन्न पक्षों को ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह उद्योग धीरे–धीरे एक विशेष तरह के संकट की ओर बढ़ रहा है। यह संकट की स्थिति ऐसी है कि चाहे शहरों में दूध की उपलब्धि कम नहीं हो, पर दूध बेचने वाले पशुपालकों की आजीविका पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारत में डेयरी उत्पादन में अगले दशक के दौरान सबसे अधिक असर इस समय विचाराधीन भारत व यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार समझौते का पड़ सकता है।

यूरोपियन यूनियन में दूध बेचने वालों के बड़े फार्म होते हैं जिन्हें भारी सब्सिडी मिलती है। अतः भारत के छोटे पशुपालकों को उनसे प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर करना बहुत अन्यायपूर्ण है। दोनों की स्थितियां बहुत भिन्न हैं। पर यदि मुक्त व्यापार समझौता होता है तो यूरोपियन यूनियन के दुग्ध उत्पादोंय जैसे दूध के पाउडर, बटर ऑयल, पनीर आदि पर नियंत्रण आयात–शुल्क नहीं के बराबर हो जाएगा। इससे सस्ते यूरोपियन आयात भारत के बाजार पर छा जाएंगे व भारत के दूध उत्पादकों से उनके अपने देश का बाजार ही काफी हद तक छिन जाएगा।

भारत में दूग्ध उत्पादों की सहकारी समितियों व उनसे जुड़े संगठनों ने इस बारे में सरकार को चेतावनी भी दी है। इस तरह के सबसे विख्यात संगठन गुजरात स्थित अमूल ने इस बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। आज से कुछ वर्ष पहले तक आयात का संकट बहुत विकट नहीं था क्योंकि हमारे देश के अधिकांश लोग ताजे दूध को ही पसंद करते हैं। इस कारण आयातित दूध का पाउडर सस्ता होने पर भी भारत के दूध उत्पादक यहां के बाजार में मजबूत स्थिति में थे। पर आपरेशन फ्लड परियोजना के अंतर्गत आयातित स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर ऑयल और ताजे दूध को मिलाकर दूध तैयार करने की ढांचागत व्यवस्था देश के बड़े भाग में तैयार की गई व इस तरह के भिन्न स्वाद के दूध के लिए बाजार तैयार किया गया।

आपरेशन फ्लड के किसी विरोध का यह जवाब दिया गया कि इसके अंतर्गत जो दूध का पाउडर और मक्खन यूरोप से आ रहा है, वह देश को सहायता के तौर पर मिल रहा है, उसकी बिक्री से जो पैसा मिलेगा उससे देश का डेयरी विकास होगा व दूध सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। सहकारी समितियों का गठन तो अच्छी बात थी पर इसमें भी आपरेशन फ्लड ने एक बड़ी समस्या यह पैदा की कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए संकरित गायों को मुख्य आधार बनाया। इस कारण

अच्छी दुधारू देसी नस्ल की गायों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सका।

यह गलती बहुत महंगी पड़ी क्योंकि अपने देश की जलवायु और यहां की स्थितियों में देसी नस्ल की गाएं ही अधिक उपयोगी हैं। संकरित गाय गर्म जलवायु या अन्य प्रतिकूल स्थितियों के कारण प्राय उपयोगी सिद्ध नहीं होती हैं। उसे कहीं बेहतर चारे की जरूरत होती है जो भारत के छोटे पशुपालकों के लिए बहुत महंगा पड़ता है।

देसी गाय की अनेक अच्छी नस्लें अपेक्षाकृत कम चारे से बेहतर लाभ देती हैं। दूध उत्पादन की तुलना प्रतिदिन के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, अपितु अनुमानित जीवनकाल के आधार पर करनी चाहिए और इस दृष्टि से भी देसी गाय अधिक अनुकूल हैं। जहां देश के दुधारू पशुओं के लिए खली की कमी थी वहां पर्याप्त खली न उपलब्ध कराकर इसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया गया। विभिन्न कारणों से भूसे की कमी भी बढ़ती गई।

हरित क्रांति की बौनी प्रजातियों से कम चारा मिलने लगा। फसल काटने में हारवेस्टर के उपयोग के कारण भी चारे की बहुत क्षति हुई। आपरेशन फ्लड ने देश में पाउडर, बटर ऑयल व ताजे दूध को मिलाकर शहरों में अधिक दूध उपलब्ध करवाने का ढांचा तो विकसित किया, पर दुधारू पशुपालन की इन बुनियादी समस्याओं को हल नहीं किया। आपरेशन फ्लड के अंतर्गत इस तरह के बदलाव लाए गए जिससे एक तरह से भविष्य के लिए यूरोपियन यूनियन के दुग्ध उत्पादों के बाजार की भूमि तैयार हो जाए। पर भारत के पशुपालकों और कृषकों के लिए यह

n'k d nèk dk cktkj ;fn LFkkuh; fdlkuk o i'kqikydk d gkFk l fNuk rk mudh vkfFkd fLFkfr cgqr {kfrxLr gksxhA

सहनीय नहीं है कि देश के दूध बाजार पर विदेशी नियंत्रण होने दिया जाए। अतः यदि मुक्त व्यापार समझौते से या अन्य किसी उपाय से ऐसा कुप्रयास होता है, तो अहिंसक आंदोलन से उसका व्यापक विरोध होना चाहिए।

दूध व डेयरी के कार्य की भारतीय गांवों में तीन बड़ी उपलब्धियां हैं। एक तो इनसे लोगों की महत्वपूर्ण पोषण आवश्यकता पूरी होती है। जिन्हें घी व दूध न भी मिले, उन्हें पहले निशुल्क छाछ के रूप में कुछ जरूरी प्रोटीन तो मिल ही जाता था। दूध व डेयरी कार्य की दूसरी प्रमुख भूमिका यह रही है कि इससे निरंतरता से कुछ नकद आमदनी होती रहती है। अतः देश के दूध का बाजार यदि स्थानीय किसानों व पशुपालकों के हाथ से छिना तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत क्षतिग्रस्त होगी।

तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देसी गोवंश को जब तक प्रोत्साहन मिलता रहा तब तक बैलों की भी अच्छी उपलब्धि खेती के लिए होती रही। देसी गायों की उपेक्षा से बैलों की उपलब्धि की भी क्षति

vkijs'ku ¶yM d vrxr bl rjg d cnyko yk, x, ftll ,d rjg l Hkfo"; d fy, ;jkfi;u ;fu;u d nqXèk mRikn d cktkj dh Hkfe r;kj gk tk,A ij Hkkjr d i'kqikydk vkj Ñ"kdk d fy, ;g lguh; ugh g fd n'k d nèk cktkj ij fons'kh fu;=.k gksu fn;k tk,A

हुई। इन सब व्यापक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए देश में डेयरी व दूध के कारोबार को तथा दुधारू पशुपालन को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाना चाहिए जिससे वह किसी भी भावी संकट का सामना करने में सक्षम हो।

डेयरी के कार्य को गांवों में बुनियादी स्तर पर मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि चारे और खली की पर्याप्त उपलब्धि हो। अनेक पशुपालक शिकायत करते हैं कि चारे की महंगाई व कमी उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। किसानों को तो फिर भी अपने खेत से कुछ चारा मिल जाता है, पर भूमिहीन पशुपालकों को तो सभी तरह का चारा नकद ही खरीदना पड़ता है। देश में अब चरागाह बहुत कम रह गए हैं और चरागाह बचाने की ओर खास ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि पशुओं के लिए पीने के पानी की कमी भी बहुत से गांवों में हो जाती है। यदि हमें डेयरी के कार्य का मजबूत आधार तैयार करना है तो इन सब समस्याओं को दूर करना होगा। इसके साथ ही दूध की सहकारी समितियों को मजबूत करना चाहिए और उनमें भूमिहीन व निर्धन परिवारों को महवपूर्ण स्थान देना चाहिए।

डेयरी कार्य में आगे आने के लिए निर्धन व भूमिहीन, दलित व आदिवासी परिवारों को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। डेयरी विकास का उद्देश्य महज बाजार में दूध की आपूर्ति करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो तीन पक्षीय होना चाहिए। दूध पर्याप्त उपलब्ध हो, साथ में उसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो। सबसे जरूरी तो यह है कि दूध की उपलब्धि का आधार अपने देश के पशुपालकों को बनाया जाए और उनको दूध की उचित कीमत भी मिले। ❑

मुद्दा

जारी है अघोषित आपातकाल

D;k n'k vkikrdky l eqä gk ik;k g] D;k ykdrkf=d lLFkk,a [krj e ugh g\ D;k ukxfjdk d ekfyd vf/kdkj dpy ugh tk jg g\ D;k ifyfl ;k tekr fgl k ij mrk: ugh g\ D;k l jdkj d e=h fujd'k vkj Hk"V ugh g\ vxj gk rk fQj D;k Qd g bfnjk xk/kh vkj euekgu fl g l jdkj e\ gkykr rk igy l Hkh cnrj gA

■ अरविन्द जयतिक

आज देश के मौजूदा हाल 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा थोपे गए आपातकाल से भिन्न नहीं है. अंतर इतना भर है कि तत्कालीन सरकार ने संप्रभु संविधान को निलंबित कर लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संस्थाओं को मटियामेट किया, मौजूदा सरकार संविधान की आड़ लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं और नागरिक अधिकारों का गला घोंट रही है।

आपातकाल के चार दशक गुजर जाने के बाद देश में एक नई पीढ़ी आयी है। वह इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल से अपने को कितना जोड़ पायी है यह कहना तो कठिन है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति उसकी सजगता लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। फिर भी चार दशक पहले लूटी गयी लोकतंत्र की लाज से नई पीढ़ी को अंजान नहीं रहना चाहिए। जो राष्ट्र अपने अतीत से सबक नहीं लेता वह मर जाता है। नई पीढ़ी को जानना–समझना जरूरी है कि किस तरह एक निर्वाचित सरकार ने सत्ता अहंकार में निरंकुशता की हदें पार कर देश पर आपातकाल थोप दिया था।

xjhch] cjkstxkjh vkj Hk[kejh dk foLrkj gvk gA xjhch d dkj.k ekr dk lkeuk dju okys fo'o d lcl s i.k ykxk e ,d frgkbl l[;k Hkkjrh;k dh gA rdjhcu 30 djkM l vf/kd ykx [kkyh isV lk jg g] tcfd ljdkjh xkknke e gj lky lkB gtkj djkM #i, dk vukt lM jgk gA vkdM crkr g fd xjhc rcd d cPpk vkj efgykvk e dik"k.k vR;r fuEu vYhdh n'kk l Hkh cnrj gA

12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को भ्रष्ट तरीके से जीतने का आरोप लगाकर रद्द कर दिया। साथ ही उन पर छह साल चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध भी लगाया। इस फैसले से गांधी बौखला गयीं, उनका सत्तात्मक अहंकार जाग उठा। लेकिन उनके पास विकल्प सीमित थे या तो वह न्यायालय के फैसले का सम्मान कर अपने पद से इस्तीफा देतीं या संविधान का गला घोंट तानाशाही लादती।

उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। संविधान को निलंबित कर बगैर कैबिनेट की मंजूरी के ही देश पर आपातकाल थोप दिया। निरंकुशता पर उतारू इंदिरा गांधी सरकार की पुलिस ने जयप्रकाश नारायण समेत तमाम उन लोकतंत्र समर्थकों को मीसा और डीआइआर कानूनों के तहत जेल में ठूंस दिया जो सरकारी तानाशाही का विरोध कर रहे थे। प्रेस की आजादी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं समाचार पत्रों में संपादकीय स्थान का रिक्त होना भी सरकार अपने खिलाफ विद्रोह मानती थी।

सरकार ने लोकतांत्रिक मर्यादा को ताक पर रख लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ताला झुला दिया। सरकार की पुलिसिया फौज क्रूरता से राजनीतिक विरोधियों को कुचलने लगी। मोरार जी देसाई के शासन में गठित शाह आयोग की रिपोर्ट में दिल दहलाने वाले निरंकुशता का भरपूर जिक्र है। कहा गया है कि आपातकाल के दौरान गांधी जी के विचारों के साथ–साथ गीता से भी उद्धरण देने पर पाबंदी थी।

सत्ता के चाटुकारों द्वारा प्रचारित किया गया कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन फासिस्टवादी है। ठीक उसी तरह जैसे आज अन्ना के आंदोलन को मौजूदा सरकार के खेवनहार फासिस्ट बताते हैं इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को मुठ्ठी में कैद करने के लिए संवैधानिक नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए चौथे नंबर के जज को मुख्य न्यायाधीश बनाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर सिगनादेश जारी किए जाने के बाद वह और बौखला उठीं। उन्होंने संविधानेत्तर सरकार चला रहे अपने पुत्र संजय गांधी की मदद से उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मटियामेट करना शुरू कर दिया जिसे उनके पिता और देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संवारने में दिलचस्पी दिखायी थी।

बिना अभियोग चलाए ही लाखों लोग जेल में भेंज दिए गए। संवैधानिक संस्थाएं इंदिरा गांधी की सुर में सुर मिलाने लगीं लेकिन लोकतंत्र में तानाशाह हमेशा हारता है, तो इंदिरा गांधी की तानाशाही बरकरार कैसे रह सकती थी। 1977 के आम चुनाव में देश की जनता ने उन्हें मचा

Hk"Vkpkj dk f[kykQ vkokt mBkus okys vkanksyudkfj;ksa dks ljdkj lkaçnkf;d ?kksf"kr dj jgh gSA lPpkbZ is'k djus okys i=dkjksa vkSj vkjVhvkbZ dk;ZdrkZvksa dks VkjxsV dj jgh gS- D;k ;g bl ckr dk lcwr ugha gS fd ns'k v?kksf"kr vkikrdky ls tw> jgk gS

चखा दिया। कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जयप्रकाश के आंदोलन ने तानाशाही की कमर तोड़ दी, लेकिन असल सवाल अब भी जस का तस है।

क्या देश आपातकाल से मुक्त हो पाया है, क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में नहीं हैं? क्या नागरिकों के मौलिक अधिकार कुचले नहीं जा रहे हैं? क्या पुलिसिया जमात हिंसा पर उतारू नहीं है? क्या सरकार के मंत्री निरंकुश और भ्रष्ट नहीं है? अगर हां तो फिर क्या फर्क है इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह सरकार में? हालात तो पहले से भी बदतर हैं।

गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी का विस्तार हुआ है। गरीबी के कारण मौत का सामना करने वाले विश्व के संपूर्ण लोगों में एक तिहाई संख्या भारतीयों की है।

turk n[k pqdh gS fd fdl rjg V&th LisDVªe vkoaVu] dkWeuosYFk xsEl vkSj dks;yk vkoaVu ?kksVkys esa vjcksa&[kjcksa dk yqV epkA çèkkuea=h us viuk lfpo vkSj ea=h;ksa dks ekQZr lhchvkbZ dh LVsVl fjiksVZ ls NsM+NkM+ djk;hA cnys esa lhchvkbZ dks lokSPp vnkyr ls yrkM+ [kkuh iM+hA

तकरीबन 30 करोड़ से अधिक लोग खाली पेट सो रहे हैं, जबकि सरकारी गोदामों में हर साल साठ हजार करोड़ रुपए का अनाज सड़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि गरीब तबके के बच्चों और महिलाओं में कुपोषण अत्यंत निर्धन अफ्रीकी देशों से भी बदतर है।

भारत के संदर्भ में इफको की रिपोर्ट कहती है कि कुपोषण और भुखमरी की वजह से देश के लोगों का शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति शर्मिंदा करती है। 119 विकासशील देशों में उसे 96वां स्थान प्राप्त है। सूची में स्थान जितना नीचा होता है सम्बन्धित देश भूख से उतना ही अधिक पीड़ित माना जाता है।

विश्व बैंक ने 'गरीबों की स्थिति' नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में करीब 120 करोड़ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और इनमें एक तिहाई संख्या भारतीयों की है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्धन लोग 1.25 डॉलर यानी 65 रुपए प्रतिदिन से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। यह सब सरकार की असफल आर्थिक नीतियों का नतीजा है। देश का लूटा गया धन विदेशी तिजोरियों में बंद है। जनता उसकी वापसी की मांग कर रही है और सरकार उन पर लाठी बरसा रही है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आंदोलनकारियों को सरकार सांप्रदायिक घोषित कर रही है। सच्चाई पेश करने वाले पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है. क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि देश अघोषित आपातकाल से जूझ रहा है? कालेधन के खिलाफ आंदोलन चला रहे योगगुरु रामदेव और उनके सत्याग्रहियों पर जिस तरह दिल्ली के रामलीला मैदान

में जुल्म ढाया गया क्या वह आपातकाल की याद नहीं दिलाता है?

जिस तरह लोकपाल पर सरकार की हठधर्मिता उजागर हो रही है और नागरिक समाज विवश है वह एक जिंदा लोकतंत्र का प्रमाण नहीं है। जिस सत्याग्रह और अनशन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई का सबसे ताकतवर हथियार बताया था, आज उन्हीं के नाम की माला जपने वाली यूपीए सरकार उसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रही है।

गांधी ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया था। क्या उनके नाम की माला चलने वाली सरकार उस रास्ते पर चल रही है, क्या उसका अंतःकरण शुद्ध है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह सत्याग्रहियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है? वह लोकभावना का मजाक क्यों उड़ा रही है? क्या गांधी ने कभी लोकभावना का मजाक उड़ाया था? याद रखना होगा कि लोकतंत्र की बहाली और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अनगिनत बार अनशन किया।

लूटमार व शोषण की पोषक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब गांधी का अनशन और आंदोलन लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ नहीं हो सकता तो फिर भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ अन्ना और रामदेव का आंदोलन लोकतंत्र के विरुद्ध कैसे कहा जा सकता है? पर सरकार की दृष्टि में वह हर समाजसेवी और आंदोलनकारी राजद्रोही है जो सरकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ मुखर है।

कांग्रेसी सत्ता प्रतिष्ठानों के व्यूहकारों का जब नंगापन उजागर हो गया है, तो वे अब उसे छिपाने के लिए समाजसेवियों और आंदोलनकारियों को आरएसएस का व्यक्ति बता उनके आंदोलन को लक्षित कर रहे हैं। जनता सबकुछ देख–समझ रही है। वह देख चुकी है कि किस तरह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर एक भ्रष्ट अधिकारी को नियुक्त करने का प्रयास किया गया और अदालत से लताड़ खाने के बाद कदम पीछे हटाया गया।

जनता देख चुकी है कि किस तरह टू–जी स्पेक्ट्रम आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला आवंटन घोटाले में अरबों–खबरों का लूट मचा। प्रधानमंत्री ने अपने सचिवों और मंत्रियों के मार्फत सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट से छेड़छाड़ करायी। बदले में सीबीआई को सर्वोच्च अदालत से लताड़ खानी पड़ी। देश यह भी देख रहा है कि सत्ता के नराधम पुलिसिया क्रूरता से आमजन को रौंद रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय उसकी तुलना जलियावाला बाग कांड से कर रहा है? सवाल लाजिमी है कि क्या इस बनावटी लोकतंत्र में नागरिक अधिकार सुरक्षित रह गए हैं? अगर नहीं तो कहना गलत होगा कि देश आपातकाल से मुक्त है। ❑

¼i"B 28 dk 'k"k tkjh- - - -½

घट रही है विकास दर. . .

यह है कि मात्र 20 फीसदी श्रमिकों को कुशलता का प्रशिक्षण मिलता है। दूसरी ओर, चीन में 91 फीसदी लोग कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित हैं।

उल्लेखनीय है कि जनसांख्यिकीय बढ़त हासिल करने के साथ–साथ दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी रखने वाला भारत कौशल प्रशिक्षण की कमी दूर कर आर्थिक विकास को भारी ऊंचाई दे सकता है। देश की जनसंख्या में पचास प्रतिशत से ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जिनकी उम्र पच्चीस से कम है। ये प्रतिभाएं सस्ते एवं गुणवत्तापूर्ण काम से जहां आउटसोर्सिंग को बढ़ाकर नई कमाई का ढेर लगा सकती हैं, वहीं विदेशी अर्थव्यवस्थाओं का सहारा बनकर डॉलर, यूरो और येन की कमाई कर देश को भेज सकती हैं। यह जरूरी है कि अच्छे रोजगार के लिए सरकार गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करे। चूंकि औसत योग्यता वाले युवाओं के लिए व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम करने के बाद रोजगार की डगर पर अवसरों को पाने की अपार संभावनाएं हैं, अतएव उन्हें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों से शिक्षित–प्रशिक्षित करना होगा। गांवों में काफी संख्या में जो गरीब, अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोग हैं, उन्हें बेहतर रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित करना होगा।

वैश्विक उद्योग–व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन के रूप में पेशेवर और कौशल प्रशिक्षण से सुसज्जित देश की नई पीढ़ी देश और दुनिया के आर्थिक विकास की सहभागी होगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वैश्वीकरण के इस दौर में रोजगार विहीन विकास से आर्थिक विषमता की जो स्थिति पैदा हो रही है, उससे देश के ढेर सारे बेरोजगारों का असंतोष किसी भी वक्त उग्र रूप धारण कर सकता है। अतएव सरकार को संसद और उसके बाहर रोजगार विहीन विकास के प्रति गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, साथ ही, उसके निराकरण के ठोस उपाय भी करने चाहिए। ❑

दब्बूपने से नहीं चलने वाला है काम

Hkkjr vefjdk lc/kk e lerk& Hkko d vHkko d dkj.k gh cgr l vefjdh bjkn ijoku ugh p< ikrA phu d lkFk nkLrh dh ihx c<ku e fDyVu] c'k vkj vkckek rd >du dk r;kj jgr g yfdu nfu;k d lcl cM ykdrkf=d jk"V dk cjkcjh d nt ij j[ku e Hkh vefjdk dk ldkp g le> ugh vkrk fd Hkkjr dk fon'k e=ky; lj{kk ifj"kn dh LFkk;h lnL;rk d ely ij vefjdk dk D;k ugh nckrk g

■ डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अमेरिका के विदेश मंत्री बनने के बाद जॉन कैरी की यह पहली भारत–यात्रा थी। जॉन कैरी सीनेट की शक्तिशाली विदेश–संबंध समिति के बरसों अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भारत–अमेरिकी परमाणु समझौता करवाने में सक्रिय भूमिका अदा की थी। इस दृष्टि से उनकी भारत–यात्रा काफी महत्वपूर्ण थी लेकिन इससे नाटकीय नतीजों के सामने आने की संभावना कम ही थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि कैरी की भारत–यात्रा निर्थक रही।

ठीक है कि किसी नए बड़े समझौते पर दस्तखत नहीं हुए लेकिन दोनों सरकारों के बीच हुए कई ऐतिहासिक समझौतों को, जो अब तक अधर में लटके हैं, परवान चढ़ाने की बात हुई। भारत–अमेरिकी संबंधों की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि परमाणु सौदा माना जाता है। इसके खातिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगाकर कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को भी नाराज कर दिया था। इस सौदे को संपन्न हुए चार साल हो गए लेकिन अब तक यह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इसके मार्ग में दो बड़ी कठिनाइयां हैं।

अमेरिकी संस्थाओं को भारत की वे शर्तें मंजूर नहीं हैं, जिनके मुताबिक परमाणु–दुर्घटनाओं के लिए उन्हें काफी मुआवजा देना पड़ेगा और दूसरा, वेस्टिंग हाउस द्वारा गुजरात में तथा जनरल इलेक्ट्रिक्स द्वारा आंध्र में छह–छह परमाणु भट्ठियां लगाने को अमेरिकी परमाणु नियामक आयोग की स्वीकृति अब तक नहीं मिली है। सलमान खुर्शीद और कैरी की बातचीत से संकेत मिलते हैं कि ये मुद्दे सितम्बर–अक्टूबर तक सुलझा लिए जाएंगे। उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री की वाशिंगटन–यात्रा का भी कार्यक्रम बन रहा है। परमाणु सौदे को अमली जामा पहनाने के लिए भारत के मुकाबले अमेरिका ज्यादा बेकरार है। अमेरिका को करोड़ों–अरबों डॉलर का फायदा तो है ही, भारत पर उसकी कूटनीतिक और राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी।

इस सौदे के बदले भारत चाहता है कि वह परमाणु सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य बना लिया जाए, मिसाइल तकनीक नियंत्रण एजेंसी और वाजेनार व्यवस्था का अंग भी बन जाए। अमेरिका ने भारत का समर्थन तो किया है लेकिन जॉन कैरी ने न अपने भाषण में, न संयुक्त वक्तव्य में और न व्यक्तिगत बातचीत में भारत को आश्वासन दिया है कि वह उसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाने का समर्थन करेगा, जबकि अमेरिका के अभिन्न सहयोगी फ्रांस जैसे कई राष्ट्र भारत को इस बाबत स्पष्ट आश्वासन दे चुके हैं। आखिर अमेरिका भारत को समझता क्या है?

भारत पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता है। वह तो बराबरी के मित्र की तरह रह सकता है। इस समता–भाव के अभाव के कारण ही बहुत से अमेरिकी इरादे परवान नहीं चढ़ पाते। चीन के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाने में क्लिंटन, बुश और ओबामा तक झुकने को तैयार रहते हैं लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र को बराबरी के दर्जे पर रखने में भी अमेरिका को संकोच है। समझ नहीं आता कि भारत का विदेश मंत्रालय सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मसले पर अमेरिका को क्यों नहीं दबाता है? यह मामला भारत ही नहीं, संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन का है, विश्व राजनीति को नई दिशा देने का है। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच भारतीय कंपनियों के आईटी विशेषज्ञों के वीजा के सवाल पर भी बात हुई लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी कैरी ने स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया।

अमेरिकी संसद में जिस आव्रजन विधेयक को लाने की बात है, अगर वह जस का तस पास हो गया तो भारतीय विशेषज्ञों को अमेरिका जाने में बड़ी दिक्कत होगी। इस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सूचना तकनीक को, जो भारतीयों का योगदान मिल रहा है, वह

घटेगा, लेकिन ओबामा स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जिससे अमेरिका का ही नुकसान ज्यादा होगा। इस मुद्दे को भी 12 जुलाई की उस बैठक के लिए टाल दिया गया है, जो वाशिंगटन में बड़ी कंपनियों के मुख्य अधिकारियों के बीच होनी है। इस प्रकार दोनों देशों में पूंजी–विनियोग की संधि भी टल गई है।

अमेरिकी दवा–निर्माता कंपनियों के मामले को अमेरिकी अफसरों ने जमकर उठाया। वे चाहते हैं कि भारत की उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगे, जो कैंसर आदि की दवाएं यहीं बना लेती हैं। जो दवाई अमेरिका में लाखों रुपए की बिकती हैं, वे भारत में कुछ हजार में ही बन जाती हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं बताया है।

अमेरिकियों को डर है कि दूसरे देशों के दवा निर्माता भी यही करने लगे तो अमेरिका का खरबों डॉलर का दवा–धंधा चौपट हो जाएगा। इस मामले में भी भारत सरकार का रवैया दो–टूक होना चाहिए।

यदि अमेरिकी नेता अपनी कंपनियों का धंधा बचाने के लिए खुले में खम ठोंक सकते हैं तो हम अपने गरीब लोगों की जान बचाने के लिए मुंहफट क्यों नहीं हो सकते? तालिबान से सीधी अमेरिकी बातचीत के सवाल पर भारत का रवैया दबा–दबा सा रहा लेकिन हामिद करजई की जवांमर्दी ने जॉन कैरी को भारत में सफाई देने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकियों और पाकिस्तान की मदद से जब कतर की राजधानी दोहा में तालिबान ने दफ्तर खोल लिया तो करजई ने अमेरिका से चल रही अपनी सुरक्षा–वार्ता भंग कर दी।

अब कैरी ने यह सफाई पेश की है कि तालिबान से असली वार्ता तो अफगान सरकार ही करेगी बशर्त वे लोग अफगान–संविधान मानें, हिंसा त्यागें और अल– कायदा से संपर्क तोड़ें। वास्तव में अमेरिका के लिए सिर्फ तीसरी शर्त ही मुख्य शर्त है। उसे तो अपना उल्लू सीधा करना है। वह अफगानिस्तान से सम्मानपूर्वक वापसी चाहता है। उसे तालिबान की किसी अन्य बात से एतराज नहीं है।

tgk rd dN vU; çe[k fon'kh ekeyk dk loky g] Hkkjr dh jk; vefjdk l fHkUu gA tl bjku] lhfj;k] phu lcèkh ekeyk e! Hkkjr u jk; tkfgj dh g yfdu nch tcku l! de l de viu {k= d ekeyk e Hkkjr dk nCciu 'kkHkk ugh nrkA mlu vkradokn d fo#) lhèkh dkjokbl dh ckr l;ä foKfIr e D;k ugh dgh

पांच साल के तालिबानी शासन के दौरान वाशिंगटन और काबुल के संबंध मधुर ही रहे। तालिबान के शीर्ष नेताओं से वाशिंगटन का संपर्क कायम रहा। उन दिनों अमेरिकी कंपनियां मध्य एशिया के राष्ट्रों से तेल और गैस अफगानिस्तान पाकिस्तान होकर हिंद महासागर तक लाना चाहती थीं। अमेरिका को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि काबुल में तालिबान का राज है या मुजाहिदीन का। अब भी वह अफगान सरकार को दरकिनार कर अंदर ही अंदर तालिबान से समझौता चाहता है। उसकी इस गुप्त–कूटनीति का दुष्परिणाम क्या होगा, वह अच्छी तरह जानता है।

उसे पता है कि तालिबान का मनोबल ऊंचा होगा और करजई सरकार का नीचा। अफगान फौज और पुलिस भी घबराहट महसूस करेंगी। अगर तालिबान का काबुल पर कब्जा हो गया तो सबसे ज्यादा खतरा भारत को ही होगा। कैरी कुछ भी कहें, भारतीय नीति–निर्माताओं को उक्त बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। क्या भारत के विदेश मंत्रालय के पास कोई सुनिश्चित अफगान–नीति है? वह अमेरिका के भरोसे रहा तो पछताए बिना न रहेगा। उसे अमेरिका के विशेष दूत जेम्स डोबिन के साथ दो–टूक बात करनी चाहिए। जहां तक कुछ अन्य प्रमुख विदेशी मामलों का सवाल है, भारत की राय अमेरिका से भिन्न है। जैसे ईरान, सीरिया, चीन संबंधी मामलों में!

भारत ने राय जाहिर की है लेकिन दबी जुबान से! कम से कम अपने क्षेत्र के मामलों में भारत का दब्बूपन शोभा नहीं देता। उसने आतंकवाद के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की बात संयुक्त विज्ञप्ति में क्यों नहीं कही? कैरी का यह कथन आपत्तिजनक नहीं है कि भारत और पाक एक–दूसरे के यहां पूंजी लगाएं, लेकिन इसे देखकर अन्य देश भी पूंजी लगाएंगे, यह कौन–सा तर्क है? इसी प्रकार अमेरिका को ईरान के विरुद्ध सनक सवार है। जैसे उसने सद्दाम पर रासायनिक हथियारों का झूठा आरोप लगाया था, वैसे ही अब ईरान पर परमाणु बम बनाने का इल्जाम लगा रहा है।

भारत को चाहिए कि अमेरिका के प्रतिबंधों का साथ देने की बजाय वह दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ का काम करे। कैरी की यात्रा के दौरान भारत यह पहल कर सकता था लेकिन जिस सरकार के हाथ से घरेलू मामलों की लगाम छूट चुकी है, उससे विदेशी मामलों में पहल की क्या उम्मीद की जाए? ❑

रपट

vkbZ-ih-,y ds uke ij m|ksxifr] jktusrk] vfHkusrk] f[kykM+h ns'k dh turk dks ywV jgs % Mh-ds- fo'odekZ

Lons'kh tkxj.k eap us tyk;k iqryk ,oa gqbZ uqDdM+ lHkk

जबलपुर : आज देश में 80 लाख नौजवान प्रतिवर्ष बेरोजगारी की भीड़ में षामिल होते चले जा रहे हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। देष विदेषी कर्ज में डूबता जा रहा है, ढाई लाख से अधिक किसान कर्जे से तंग आकर आत्महत्या कर चुके है। दूसरी ओर आई.पी.एल के नाम पर उद्योगपति, राजनेता, अभिनेता, खिलाड़ी देष की जनता को लूट रहे है, उक्त विचार स्वदेषी जागरण मंच के मध्यप्रदेष के सहसंयोजक डी.के. विष्वकर्मा (देवेन्द) व्यक्त करते हुए कहा कि आई.पी.एल. के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। इसी सभा में अमित कोरी. प्रषांत तिवारी ने आई.पी.एल. पर प्रतिबंध की मांग की एवं पंकज नेमा के द्वारा आई.पी. एल. की सी.बी.आई. की मांग करते हुये आई.पी.एल. पर लगे पैसे को जब्त करने की मांग लेबर चौक गढ़ा में आयोजित स्वदेषी जागरण मंच के आई.पी.एल. के विरोध में पुतला दहन एवं नुक्कड़ सभा में व्यक्त किये गये।

कार्यक्रम में बलराम पटेल, कोषलेष, राजेष ठाकुर,, पप्पू कोरी, दीपक यादव, नवीन रिछारिया, गंगा प्रजापति, रूपेन्द्र नंदा, राजेष षर्मा, राघवेन्द्र चौहान, मोहन चक्रवेष, अनिल उपाध्याय, गया प्रसाद नंदा, नितिन, अक्षय राव, कमलेष यादव आदि उपथित थे। **iLrqfr% vfer dksjh**

^Lons'kh okyk* bl fopkj dk ekuus ds fy, rS;kj ugha gS fd fodkl dk if'peh ekMy lkoZHkkSe gS vkSj nqfu;kHkj ds yksxksa dks mlds udy djuh pkfg,A gkykafd os lkaLÑfrd vknku&iznku dks Lohdkjrs gSa] exj bl ckr ij tksj nsrs gSa fd gj lekt dh viuh laLÑfr gksrh gS vkSj gj ns'k dh iz×kfr vkSj fodkl ds ekMy dks mlh ns'k ds lkaLÑfrd eY;ksa ds lkFk rkjrE; gksuk pkfg,A vk/kqfud cuus dk eryc if'pehdj.k ugha gSA os if'pe ds fgr esa] fofHké laLÑfr;ksa vkSj jk"Vªh; igpkuksa dks] xzs&eSu djus dh dksf'k'kksa dk fojks/k djrs gSaA

& jk"Vª_f"k nÙkksiar BsaxM+h